



केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक

राज्यसभा से सीएपीएफ बिल पास

नई दिल्ली। सीएपीएफ में शामिल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से संबंधित द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए इसे बलों का बेहतर मैनेजमेंट, प्रमोशन में फायदा और कार्यकुशलता को बढ़ाने वाला बताया। हालांकि अर्धसैनिकों बलों के अधिकारियों के संगठन अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने इसे काला बिल बताया है। संगठन ने कहा कि इसके विरोध में नौ अप्रैल को राजघाट पर शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा।

आठ घंटे तक चर्चा

राज्यसभा में बिल पर आठ घंटे तक चर्चा की गई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की तरफ से 36 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा, शर्तों और प्रमोशन से जुड़े इस विधेयक के



बारे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि यह बलों के हित में लाया गया है। उन्होंने कहा कि बलों के ढांचे की जो परिकल्पना देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसी के अनुरूप ही सीएपीएफ में सेना और आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव किया गया है कि भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जाए। जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया। इससे पुलिस बलों में और बेहतर कैडर मैनेजमेंट और कार्यकुशलता बढ़ सकेगी।

वित्तीय लाभ बाधित नहीं होंगे

गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक से कहीं से भी वित्तीय लाभ बाधित नहीं होंगे। केंद्र सरकार सीएपीएफ अधिकारियों के प्रमोशन, वरिष्ठता आदि के लिए नियम बना सकेगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने आईपीएस की तुलना में सीएपीएफ अधिकारियों के दर से प्रमोशन मिलने के मसले पर कहा कि इससे उनके प्रमोशन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। सीएपीएफ में ग्रुप ए में सामान्य तौर पर चार प्रमोशन मिलते हैं जिसमें उम्र के हिसाब से कुछ को पांचवां प्रमोशन भी मिल जाता है। समय पर प्रमोशन ना मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि

कुछ मामलों के कोर्ट में विचाराधीन होने, वरिष्ठता को लेकर विवाद और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कारणों से कई बार कुछ अफसरों के प्रमोशन देरी से हो पाते हैं।

11 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया

मंत्री ने यह भी बताया कि पहले बलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ से दो साल का वक्त लग जाता था, जो की अब घटकर 11 महीने का रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सीमाओं तथा अंदरूनी सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के हाथों को पहले की कांग्रेस सरकारों ने बांध रखा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मजबूत अधिकार दिए हैं। एएपीडब्ल्यू के अध्यक्ष और सीआरपीएफ से रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि सबसे पहले तो बिल के बारे में सदन में गृह राज्य मंत्री की जगह खुद गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए था। उनसे बातें और स्पष्ट होती।

अमित शाह ने खुद भरा जनगणना की पहली प्रक्रिया का फॉर्म



नई दिल्ली। जनगणना-2027 शुरू हो चुकी है, जिसका हिस्सा बनते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज खुद अपने घर से इस प्रक्रिया का पहला फॉर्म भरा। फॉर्म भरने का वीडियो रिकॉर्ड कर अमित शाह ने इसे अपने

सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर भी किया। गृहमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि वे भी इस तरह डिजिटल माध्यम से अपना जनगणना फॉर्म भरे। दरअसल, आज से जनगणना की पहली प्रक्रिया शुरू हुई

है। इसके तहत ही गृहमंत्री अमित शाह ने ‘आवास गणना’ का फॉर्म भरा। गृहमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्व-गणना का फॉर्म भरा। गृहमंत्री ने आगे कहा कि भारत की विकास यात्रा को गति देने और प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने में इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों से इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही जनगणना की टीम आपके घर भी आएगी। आप भी इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई जरूरी जानकारीयां प्रदान करें। उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए कहा कि आप लिंक के माध्यम से स्वयं भी फॉर्म भर सकते हैं।

पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर ब्लास्ट

सऊदी, तुर्की, जापान ने भरी हुंकार

मीडिया



अपने शक्तिशाली सहयोगियों पर आख मूंदकर भरोसा करना चाहिए? ट्रंप प्रशासन की अनिश्चितता और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच, अब अपनी संप्रभुता बचाने के लिए खुद के परमाणु हथियार बनाने का विकल्प सबसे ऊपर आ गया है। यह शीत

युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था से एक बहुत बड़ा भटकवा है। एक वक्त था जब कई देश अमेरिका की परमाणु छतरी के नीचे खुद को महफूज मानते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। यूरोप में जर्मनी और पोलैंड डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त अपने हाथ खींच सकता है। वहीं, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया की चिंताएं भी चरम पर हैं। खुद

अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं कि वह 33 साल के अंतराल के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। रूस की पोसीडॉन अंडरवाटर ड्रोन और ब्यूरेवेस्टनिक क्यूज मिसाइल जैसी तकनीक ने अमेरिका की नॉट उड़ा दी है। सऊदी अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर ईरान बम बनाता है, तो वे भी पीछे नहीं रहेंगे। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एथना-प्रशांत क्षेत्र में आग में घी डालने का काम किया है।



असम में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बागान दौरा चर्चा का केंद्र बन गया है। डिब्रुगढ़ पहुंचने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री ने दिन की शुरुआत एक चाय बागान के दौरे से की, जहां उन्होंने महिला कामगारों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ीं, उनसे बातचीत की और सेल्फी भी खिंचवाईं। चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा, कि हमें चाय बागान के हर एक परिवार की कोशिशों पर बहुत गर्व है।

परमाणु हथियारों की होड़ का जिन्न आया बोटल से बाहर

नई दिल्ली। अमेरिका-इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। वहीं ईरान भी लगातार उनके हमलों का जवाब पूरी ताकत से दे रहा है। इस युद्ध ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। पिछले एक साल में अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर दो बड़े हमले किए। इन हमलों का मुख्य मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना था, जिसे अमेरिका और इजराइल अपने लिए खतरा मानते हैं। ईरान में पिछले पांच हफ्तों से सैन्य अभियान जारी है।

रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का मानना है कि इस जंग ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ के उस जिन्न को बोटल से बाहर निकाल दिया है, जिसे दशकों तक काबू में रखने की कोशिश की गई थी। ईरान में शासन बदलने और उसके परमाणु कार्यक्रम को जमींदोज करने की जिद अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक के देश अपनी परमाणु नीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर हैं। कई देश अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें

टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन



नई दिल्ली। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का हाथ थाम लिया। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले यह एक बेहद अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। पेस के लिए पार्टी की राजनीति कोई नई बात नहीं है। कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पेस की हालिया मुलाकात के बाद से ही इस कदम की काफी वक्त से अटकलें लगाई जा रही थीं। लिएंडर पेस के बीजेपी ज्वाइन करने की टाइमिंग काफी अहम है। साल 2021 में वह पहले भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने भाजपा के लिए ज़ोर-शोर से प्रचार किया था। हालांकि, उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। अब भाजपा में शामिल होने का उनका फ़ैसला, उस पुराने जुड़ाव से पूरी तरह अलग होने का संकेत है।

ये डबल इंजन नहीं, दोहरी गुलामी की सरकार: प्रियंका



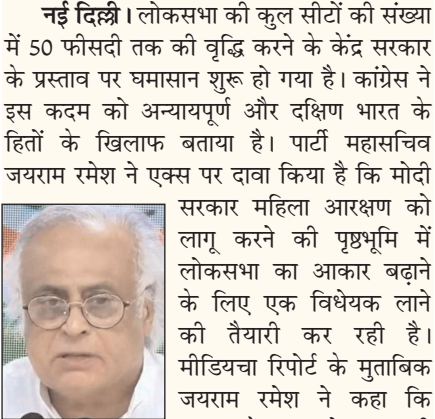
गुवाहाटी। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने असम के नाजिरा में रैली के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों की तीखी आलोचना कर लोगों से उस सरकार को खारिज करने की अपील की, जिसे उन्होंने दोहरी गुलामी की सरकार बताया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि असम के जनजातीय समुदाय वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा यह दर्जा देने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आपके लिए तभी काम करते हैं जब उन्हें इसमें अपना कोई लाभ दिखात है। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आज भी हम असम में ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपको डराए नहीं, धमकाए नहीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति न करे।

में मानद केरलवासी घोषित : राहुल



नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान खुद को मानद केरलवासी घोषित कर दिया। हालांकि उनका जन्म केरल में नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने केरल की विभाजन पर एकता की प्राथमिकता पर जोर दिया और हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने का वादा किया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि भले ही मेरा जन्म केरल में न हुआ हो, लेकिन मैं मानद केरलवासी हूँ। केरल घृणा पर प्रेम, अहंकार पर विनम्रता, क्रोध पर आशा और विभाजन पर एकता को चुनता है। इसके पहले कोझिकोड में राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को ईंधन की कीमतों में संभावित वृद्धि और मुद्रास्फीति से जोड़कर एक आगामी वित्तीय भूकंप की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है...एक त्रासदी घट रही है, और कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहाँ होगा। केरल और भारत के लोग सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है। अब से एक या दो महीने में, एक वित्तीय भूकंप आने वाला है।

लोकसभा में 50 फीसदी वृद्धि से उत्तरी राज्यों को फायदा: जयराम



नई दिल्ली। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में 50 फीसदी तक की वृद्धि करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस कदम को अन्यायपूर्ण और दक्षिण भारत के हितों के खिलाफ बताया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर दावा किया है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को लागू करने की पुष्टभूमि में लोकसभा का आकार बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। मीडियका रिपोर्ट के मुताबिक जयराम रमेश ने कहा कि प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटों में 50फीसदी की वृद्धि की जाएगी, जिसका सीधा असर हर राज्य को अवॉर्किट सीटों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं और तमिलनाडु में 39 सीट हैं। प्रस्तावित विधेयक के साथ यूपी की लोकसभा सीट की संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी जबकि तमिलनाडु में अधिकतम 59 सीट हो जाएगी। इसी तरह केरल में लोकसभा की 20 सीट बढ़कर 30 हो जाएगी, जबकि बिहार में 40 से बढ़कर 60 सीट हो जाएगी।

जनगणना का पहला चरण से शुरू



नई दिल्ली। डिजिटल जनगणना का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और पहली बार गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पहले चरण में मकानों की गणना होगी और उसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सबसे चौकाने वाली और बड़ी बात लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कही गई है। सेल्फ-एन्युमरेशन (स्व-गणना) पोर्टल पर जारी जानकारी के मुताबिक, अगर कोई कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वे अपने रिश्ते को एक स्थिर संबंध मानते हैं तो जनगणना के दौरान उन्हें

जंग से अमेरिका किसी भी तरह निकलना चाहता है, पर ईरान मौके नहीं दे रहा है

क्या ईरान से जंग हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?

कमलेश सिंह

युद्ध में हमेशा कुछ न कुछ मरता है। सबसे पहले सच्चाई मरती है। उसके ठीक पीछे इन्ज्जत लंगड़ाती हुई आती है, सीने पर नया मेडल लगाए हुए मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। बाकायदा ऐलान करके। और कुछ घंटों में खत्म। सब कुछ भारत की शर्तों पर हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। यह हैरानी की बात थी क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि उसे युद्ध नहीं लड़ना है। फिर भी पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। भारत ने जवाब दिया। कुछ दिनों में पाकिस्तान का पूरा

एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। भारतीय वायुसेना अपने टारगेट चुन रही थी जैसे नौचंदी मेले में एयर राइफल वाले स्टॉल पर गुब्बारे पर निशाने लगाए जाते हैं - आराम से, मनमाने ढंग से। तभी पाकिस्तान ने फोन उठाया और वॉशिंगटन को कॉल किया। दर्द से छुटकारा पाने के लिए। भारत की शुरुआत से यही राय थी कि उसे जंग नहीं चाहिए। वॉशिंगटन को धन्यवाद देकर कहा गया - पाकिस्तानी जनरलों से कहो कि वे भी यही बात कहें। जब पाकिस्तान के छत्रच्छ ने भारत के छत्रच्छ को फोन करके लड़ाई खत्म करने को कहा, भारत ने हामी भर दी। सीजफायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने

यह ऐलान दोनों देशों की सेना के बयान आने से पहले ही कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह कर दिखाया और कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लगे हाथ अरिम मुनिर ने भी जीत का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद को जीत का मेडल और जीवन भर के लिए ब्रम्होदड़ मार्शलक्र की पदवी भी दे डाली। यह उस शख्स के लिए बड़ा कारनामा था जिसके एयर डिफेंस मलबे में बदल चुके थे और एयरफ्रीडल पर गड्डे हो गए थे। पाकिस्तान की क़द्मशशीन पूरी हो चली। प्रधानमंत्री शरीफ भाजबाज शरीफ मुक्कुराए और मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने



मेगाफोन पर चढ़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। सब जीत रहे थे। उपमहाद्वीप के सैन्य इतिहास में यह सबसे विजयी हार थी। भारत ने ऐसा कोई नाटक नहीं किया। उसे जरूरत थी नहीं थी। सैंटैलाइट तस्वीरें सबके सामने थीं। गड्डे झूठ नहीं बोलते। वे रडार जो पाकिस्तान के आसमान की रक्षा करते

थे, किसी काम के नहीं रहे। भारत ने बस सबूत को खुलेआम पड़ा रहने दिया और अपने काम पर लग गया। ऐसा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें पता हो कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भारत के पास यह आत्मविश्वास था। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल। अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, वह ऑपरेशन सिंदूर का हॉलीवुड वर्जन है। बड़े ग्लोबल स्टेज पर, ज्यादा बजट के साथ, ज्यादा ज्वलनशील इलाके के साथ और ऐसे किरदारों के साथ कि अपोकैलिप्स नाउ भी कम ड्रामेटिक लगे। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक ही हमले में खत्म

कर दिया। वॉशिंगटन को लगा कि इससे तेहरान का हौसला टूट जाएगा, रिजीम की कमर टूट जाएगी, कमांड बिखर जाएगा और मामला जल्दी निपट जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट बदल गई। ईरान ने जवाब दिया - बदले की आग के साथ। उसने इजराइल पर हमला किया। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। उन अरब देशों पर भी हमला किया जिन्होंने चुपके से वॉशिंगटन के साथ हाथ मिला लिया था और सोचा था कि उनका भूगोल उन्हें बचा लेगा। ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों के तले जी रहा है। प्रतिबंधों का मकसद देश को भूखा मारकर घुटनों पर लाना होता है। लेकिन असल में उन्होंने ईरान को बेहद

धैर्यवान, थोड़ा रचनात्मक और अमेरिकी धमकियों से पूरी तरह बेपरवाह बना दिया। जब तुम 40 साल से सजा भुगत रहे हो, तो ओर सजा बस एक साधारण मंगलवार जैसी हो जाती है। होम्रुंज स्ट्रेट बंद हो गया। अमीर अमेरिकी-समर्थक खाड़ी देश अब समझ रहे हैं कि जिस पड़ोसी से कभी दोस्ती नहीं हो सकी, वह अंदर से दरवाजा बंद कर दे तो क्या होता है। उनका सुरक्षा गारंटर अपने बेस भी सुरक्षित नहीं रख पाया और अब सब बंद करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा। ईरान टोल वसूल रहा है। और टोल बहुत भारी है।

गेवरारोड पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर लाइन पूर्णता की ओर

कोरबा। छत्तीसगढ़ में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना गेवरारोड पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर का निर्माण अब पूरा होने वाला है. जमीन अधिग्रहण, लाइन एलाइनमेंट और बड़ी चोरी के संकटों के बाद ढेर से ही सही फिलहाल इस परियोजना का 90 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। दावा ये भी है कि इसी वर्ष के दिसंबर तक 135 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में 20 किलोमीटर को लाइन को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इसे हरी झंडी मिल गई है।

फिलहाल देश के सबसे बड़े कोयला खदानों से देश के पश्चिम क्षेत्र जिनमें राजस्थान और गुजरात सहित मध्यप्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। वहां कोयले की ढुलाई के लिए एकमात्र विकल्प कोरबा से उरगा, चांपा से

कोल लदान का बनेगा रिकॉर्ड लेकिन यात्री सुविधा विस्तार पर संशय



बिलासपुर वाली लाइन है।अब गेवरा रोड-पेंड्रा रोड के अस्तित्व में आ जाने के बाद इन खदानों से उरगा के बजाय इसके विपरीत मार्ग से सीधे पेंड्रा रोड का सफर आसान होगा।ऐसा होने पर 70 से 80 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। कोरबा शहर को बार-बार बंद होने वाले फाटक की समस्या से निजात मिलेगी।

रोड सेल के माध्यम से कोयला लदान में भी कमी

आएगी। इससे प्रदूषण का ग्राफ कुछ हद तक कम होगा। इन तमाम फायदों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे को सबसे अधिक राजस्व करने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयले की ढुलाई में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, या फिर यात्री सुविधाओं को भी इस नए ट्रैक से जोड़ा जाएगा। भले ही रेलवे की इस परियोजना की प्राथमिकता माल ढुलाई है।

बावजूद इसके वर्षों से रेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित कोरबा और आसपास के क्षेत्र को इस लाइन से काफी उम्मीदें भी हैं। लाइन पूरी होने के बाद यात्री सुविधाओं के विस्तार का एक बड़ा प्रश्न और चुनौती रेलवे के सामने खड़ा है। गेवरारोड से पेंड्रारोड तक निर्माणाधीन 135 किमी लंबी ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के पहले सेक्शन पर ट्रायल पूर्ण कर लिया गया है। इसपर डीजल इंजन से ट्रायल पूर्ण किया गया है। कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रिकल विभाग का काम अभी अधूरा होने के कारण फिलहाल डीजल इंजन से ट्रायल किया गया है। इसी तरह अलग-अलग क्षेत्र का क्रमवार ट्रायल किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों और कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट ट्रायल रन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की हत्या, अरोपियों की तलाश जारी

जांजगी-चांपा। ज़िले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपियों ने घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की थारदार हथियार से हत्या कर दी। पूरा मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के खपरी गांव का है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मुतकों की पहचान छतराम साहू और उनकी पत्नी श्याम बाई के रूप में हुई है। दोनों बीती रात अपने घर में सो रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घटना स्थल पर खून से सने पैरों के निशान



मिले हैं, जिससे आरोपियों के भागने की दिशा का अंदाजा लगाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से होली का मुखौटा भी बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा पहनकर आए थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे लूट और चोरी की नीयत से की गई हत्या मान रही है। दोनों शवों को पीएम के लिए भेज गया है।

ऑपरेशन निश्चय के तहत 10 घंटे में 4.61 करोड़ की ड्रस-संपत्ति जब्त

महासमुंद। महासमुंद जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महासमुंद पुलिस ने महज 10 घंटों के भीतर चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लगभग 686 किलो गांजा और 700 नशीली टैबलेट जब्त की है। जब्त मादक पदार्थों और परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की कुल कीमत 4 करोड़ 61 लाख 67 हजार 506 रुपये आंकी गई है।

तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ९९पैकर्स एंड मूवर्स% के ट्रक, ड्राई फरस्ट्स के कंसाइनमेंट, लग्जरी कारों और यहां तक कि मोटरसाइकिल और ट्रैन का भी सहारा लिया, लेकिन



पुलिस के सूचना तंत्र और मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने पांच अलग-अलग प्रकरणों में कुल 13 तस्करों को

कथा में हंगामा, आयोजक का पकड़ा गया कॉलर

कोरबा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में विवाद हुआ था। इस कथा का आयोजन कराने वाले आयोजक के साथ ही अभद्रता की गई। आपको बता दें कि कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री कटघोरा के अग्रसेन भवन में ठहरे हुए हैं। यहीं उनसे मिलने आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर विवाद हुआ। हालांकि इस विषय में आयोजन समिति की ओर से अब तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। लेकिन कॉलर पकड़ने का वीडियो सामने आने के बाद तरह-तरह की चर्चा है। रायपुर के बसंत अग्रवाल और आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजत अमरजीत सिंह के बीच बहस की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार अमरजीत आयोजन



समिति के संयोजक हैं और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष भी हैं। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए अग्रसेन भवन के उस कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, जहां धीरेंद्र शास्त्री मौजूद थे। इसी बात पर रायपुर के चर्चित जमीन कारोबारी बसंत अदवाल से उनकी भिड़ंत हो गई। धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा इसे लेकर दोनों में बहस हुई, खबर तो ये भी है कि दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

निवासी हैं। महासमुंद पुलिस को इस कार्यवाही में बिलासपुर पुलिस और रायपुर फ़ाइम ब्रांच का भी अहम तकनीकी सहयोग रहा। आंकड़ों की बात करें तो पिछले तीन महीनों में महासमुंद पुलिस ने अब तक 63 प्रकरणों में 40

क्रिंटल (4054 किलो) से अधिक गांजा जब्त कर 165 तस्करों को जेल भेजा है। नशे के खिलाफ महासमुंद पुलिस का यह अभियान जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित है। हम न केवल परिवहन करने वालों को पकड़ रहे हैं, बल्कि सोसं (विक्रेता) और डेस्टिनेशन (खरीददार) तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर रहे हैं।

-प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

एसईसीएल में 8.8 मिलियन टन कोयले की वृद्धि

कोरबा। एसईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र ऐसी सहायक कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसने कोयला उत्पादन, प्रेषण (आफटेक) तथा ओवरबर्डन निष्कासन (ओबीआर)-तीनों प्रमुख मानकों में एक साथ सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसईसीएल का कोयला उत्पादन 176.2 मिलियन टन रहा, जो

महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दे रहा छत्तीसगढ़ मॉडल : खडसे

जगदलपुर। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने बुधवार को तुरेनार



स्थित छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर एवं प्रगति महिला स्व-सहायता समूह के स्टॉल्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों, महिला उद्यमिता एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती रक्षा खडसे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत भी बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित विभिन्न योजनाएं, जैसे कि महतारी वंदन योजना, महिलाओं को आर्थिक संवल प्रदान कर रही हैं। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री, रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादों का निर्माण तथा लखपति दीदी योजना जैसे प्रयास महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं।रक्षा खडसे ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि स्व-सहायता समूह द्वारा रेडी टू इट निर्माण, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इन प्रयासों को नारी शक्ति के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।

इसके अलावा बस्तर ज़िले के ग्राम चिलकुटी के दौरे के दौरान उन्होंने पारंपरिक कला एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर रक्षा खडसे ने विशेष रूप से पारंपरिक लॉस्ट वैंक्स तकनीक (ढोकरा शिल्प) को निकट से देखा, जो आदिवासी कला और शिल्प कौशल की एक अद्वितीय पहचान है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा केवल कला नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति और स्थानीय कारीगरों की जीवंत विरासत का सशक्त प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा खडसे ने महिला उद्यमियों एवं स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूहों तथा पारंपरिक शिल्प के माध्यम से हो रहा यह परिवर्तन महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि का एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर खेलों इंडिया के संचालक मयंक श्रीवास्तव कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, एसडीएम बस्तर गगन शर्मा उपस्थित रहे।

केमिकल फैक्टरी में पाइपलाइन फटी, लगी आग; हर तरफ फैला धुआं

दुर्ग। दुर्ग के भिलाई के हथखोज इंजीनियरिंग पार्क स्थित थेंथिस हाइड्रोकार्बन कंपनी में पाइपलाइन फट गई और आग लग गई। घटना मंगलवार की रात की बताई जा रही है। कंपनी से धुआं निकलने लगा जिससे आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने

कंपनी पर लापरवाही का आरोप



कड़ी मशक़त के बाद केमिकल से निकलने वाले धुआं पर काबू

पाया गया। शुरुआत जांच में कंपनी प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। हथखोज के इंजीनियरिंग पार्क के थेंथिस हाइड्रोकार्बन कंपनी में केमिकल ने अचानक धुआं निकलते देख कर्मचारी के साथ इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि इसके बाद भी कंपनी प्रबंधन ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग या पुलिस को नहीं दी। लेकिन जब आस पास के लोगों

ने आग की लपटे और धुआं देखा तो इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। उसके बाद आनन-फ़ानन में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक़त के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र सिंह ने बताया कि थेंथिस हाइड्रोकार्बन कंपनी में पिंच ऑयल के लोडिंग के दौरान अचानक पाइपलाइन फटने जाने से जमीन पर फैल गई और हवा के संपर्क में आने से धुआं

निकलने लगा। धुएं से आसमान काला पड़ा गया और आसपास रहे वालों को सांस लेने में परेशान होने लगी। दमकल विभाग ने केमिकल से निकाने वाले धुंआं को काबू में पाया। दमकल विभाग को शुरुआत जांच में कंपनी प्रबंधन की लापरवाही सामने आया है। विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ भाजयुमो ने मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

दत्तेवाड़ा-सूरजपुर। नक्सल हिंसा से लंबे समय तक जूझते रहे बस्तर अंचल में अब शांति और विकास की नई सुबह देखने को मिल रही है। इसी ऐतिहासिक बदलाव के बीच भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दत्तेवाड़ा और सूरजपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा में नक्सल मुठभेड़ों में शहीद हुए वीर जवानों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को दीप प्रज्ज्वलित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दत्तेवाड़ा के जय स्तंभ चौक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ दीप जलाकर यह संदेश दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए दी गई शहादत का भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राहुल असरानी ने कहा कि देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान और सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति रही है।

सूरजपुर में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुण्ड

सूरजपुर। महुआ का सीजन शुरू होते ही जंगलों में एक बार फिर हाथियों की हलचल तेज हो गई है। महुआ के फूलों की खुशबू और स्वाद से आकर्षित होकर हाथियों के झुंड आबादी और सड़कों के नजदीक तक पहुंचने लगे हैं। ताजा मामला सूरजपुर वन परिक्षेत्र के खरगोन कला क्षेत्र का है, जहां बीच सड़क पर हाथियों का मूवमेंट देखने को मिला। कल्याणपुर-खड़गवां मुख्य मार्ग पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब चार दंतैल हाथी सड़क पार करते नजर आए। हाथियों के अचानक सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालकों ने सावधानी बरतते हुए अपनी गाड़ियां रोक दीं और हाथियों के सुरक्षित निकलने का इंतजार किया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए हाथियों के बेहद करीब पहुंच गए और सेल्फी लेने के साथ वीडियो बनाने नजर आए। यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी, क्योंकि जंगली हाथी कभी भी आक्रामक हो सकते हैं। हाथियों के गुजरने की जानकारी के बाद पहुंचा वन विभाग।

गेहूं मिसाई के दौरान थ्रेसर में महिला का बाल पट्टे में फंसा

सूरजपुर। अंतिकापुर गांव में खेत उस वक्त हादसे का मैदान बन गया, जब गेहूं मिसाई के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। मंगलवार को खेत में थ्रेसर मशीन से गेहूं निकालने का काम चल रहा था। काम के दौरान अचानक एक महिला का बाल मशीन के घूमते हुए पट्टे में फंस गया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और महिला के सिर के बाल के साथ उसका कान भी मशीन में बुरी तरह फंसकर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मशीन को बंद किया और घायल महिला को बाहर निकाला। महिला को हालत बेहद गंभीर थी, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैडन अस्पताल रेफर किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उस तुरंत वहां पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल महिला स्थानीय साहू परिवार की सदस्य है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में नेम टैग गतिविधि का आयोजन

जगदलपुर। बच्चों के प्रारंभिक विकास और उनकी रचनात्मकता को नई दिशा देने के उद्देश्य से बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में हाल ही में एक अत्यंत उत्साहजनक और प्रेरणादायक गतिविधि संपन्न हुई। तितली संस्था के सहयोग से आयोजित इस नेम टैग बनाओ पहल के माध्यम से आंगनवाड़ी के नन्हे-मुन्नों ने न केवल कला का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान की ओर भी एक मजबूत कदम बढ़ाया। इस गतिविधि के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का माहौल किसी उत्सव जैसा नजर आया, जहाँ बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को काजों पर उतारा। छोटे-छोटे हाथों ने रंग-बिरंगे स्केच और कलमों की मदद से खुद के नाम लिखे और बेहद सुंदर नेम टैग (आईडी कार्ड) तैयार किए। बच्चों द्वारा बनाए गए ये कार्ड केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उनकी मेहनत और अपनी पहचान के प्रति गौरव का प्रतीक थे। जैसे ही इन बच्चों ने अपने हाथों से बने इन आईडी कार्ड्स को गले में पहना, उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास देखने को मिला।

बस्तर के कृषि उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान

जगदलपुर। बस्तर संभाग की समृद्ध कृषि परंपरा और अद्वितीय वनोपजों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा एक वृहद निर्यात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और लक्षद्वीप प्रोड्यूसर कंपनी बकावंड के साझा सहयोग से किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य जिले में उपलब्ध अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, ताजे फलों और सब्जियों के लिए निर्यात के नए द्वार खोलना था। इस कार्यक्रम की सार्थकता इस तथ्य से और महत्वपूर्ण हो गई है कि वर्तमान वर्ष 2026 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अनुरूप, कार्यशाला में बस्तर की महिला शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

छत्तीसगढ़ नक्सली समर्पण : सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं

विकास मिश्रा

छत्तीसगढ़ में समर्पण करने वाले खूंखार नक्सली नेता गुप्पिदी उर्फ विकास से एक पत्रकार ने पूछा कि अंतिम लक्ष्य क्या था? उसने काफी सारी बातें कहीं लेकिन उस बीच में उसने यह भी कहा कि लाल किले पर लाल झंडा फहरा कर सरकार बनाना भी नक्सलवादियों का लक्ष्य था। समर्पण करने वाले नक्सलियों के और भी साक्षात्कार आप देखें तो यह स्पष्ट है कि कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है! वे अब भी अपने नजरिये की ही बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बस संघर्ष का रास्ता बदल रहे हैं।जो भी हो, यह फिर साबित हो गया है कि यदि सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई तीन साल पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की चुनौती सभा में जब यह कहा कि उनकी सरकार को मौका मिला तो वे छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या खत्म कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों ने



यही समझा कि ये चुनौती घोषणा है। मगर अमित शाह ने राज्य सरकार के सहयोग से आज वह कर दिखाया। स्वाभाविक रूप से छुटपुट नक्सली कहीं जंगलों में बचे होंगे लेकिन जंगल का करीब-करीब पूरा हिस्सा नक्सलियों से मुक्त हो चुका है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। पापा राव वो अंतिम बड़ा नक्सली था जिसने हथियार डाल दिए हैं। केवल तीन साल पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, झारखंड और

ओडिशा में छह हजार से ज्यादा सशस्त्र नक्सली सक्रिय थे। उनमें से ज्यादातर या तो मारे गए या फिर सशस्त्र बलों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए। निश्चय ही जंगलों में अब शांति लौटेली। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नक्सलवाद इस कदर फैला कैसे? क्या राज्य सरकारों या केंद्र की सरकार को नक्सलियों का फैलाव समझ में नहीं आ रहा था। क्या उनका मकसद किसी को समझ में नहीं आ रहा था? नक्सलियों ने 7 राज्यों में 1200 किलोमीटर रेड कॉरिडोर को फैला लिया और सरकारें देखती रहीं? कहते हैं कि करीब 94 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नक्सलियों का जंगल राज था। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता था। भारतीय संविधान का नही बल्कि नक्सलियों का कानून वहां चलता था। हमारे सशस्त्र बल के हजारों जवानों को नक्सलियों ने मार डाला। फिर भी सरकारें उस स्तर पर कार्रवाई करने से हिचकती रहीं, जिस स्तर पर सख्ती होनी चाहिए थी। मानवाधिकार के नाम पर ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जो हर पुलिस कार्रवाई पर तो सवाल खड़ा

करता रहा कि जुल्म हो रहा है, लेकिन नक्सली किसी जवान की हत्या कर दें तो कोई भी मानवाधिकार की बात करता ही नहीं था! दरअसल नक्सलियों ने बड़ी चतुराई के साथ व्यूह रचना की थी। उन्होंने खुद को जंगल के भीतर आदिवासियों के संरक्षक के रूप में स्थापित किया। आदिवासियों को भ्रमित करके या फिर डरा-धमका कर खुद के साथ कर लिया तो दूसरी ओर शहरों में एक ऐसी कौम खड़ी की जो इन नक्सलियों को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताती रही। सरकार को इस तरह घेर लिया गया कि वह सख्त कार्रवाई करने के पहले कई बार सोचे। यह व्यूह रचना ऐसी थी कि सरकारें खुद को असहाय महसूस करने लगी थीं। इच्छाशक्ति के अभाव ने समस्या को और गंभीर बना दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि नक्सलियों के इलाके में शाम ढलने के बाद पुलिस फोर्स के जवान कैप से बाहर निकलने के पहले न जाने कितनी बार सोचते थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। वे गोली चलाएं तो मानवाधिकार वाले दिल्ली तक कोहराम मचा दें! मगर

अमित शाह ने जब कहा कि नक्सलवाद खत्म करेंगे तो उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी फोर्स खुल कर काम करेगी। जो हथियार डालना चाहे, उसका स्वागत है लेकिन जो लड़ना चाहे, उसके लिए मौत तय है। जरूरत थी सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की ताकि नक्सलियों में खोफ पैदा हो सके। 21 मई को वह दिन भी आया जब रेड कॉरिडोर की राजधानी कहे जाने वाले अबूझमाड़ में घुसकर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर बसवराजू को मार गिराया। 10 अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मौत के घाट उतारे गए। चुन-चुन कर उन सभी को मारा गया जिन्होंने रेड कॉरिडोर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में कमान संभाली थी। अब रेड कॉरिडोर पर सुरक्षा बलों के 400 से ज्यादा कैप हैं। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए और भी कई तरह के उपाय किए गए। सबसे पहला था आर्थिक प्रहार। शासन और प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि धन के सारे स्रोतों को रोक दिया जाए। जो

संक्षिप्त समाचार

सांसद फूलोदेवी ने सांसद में की छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली/रायपुर। राज्यसभा सांसद



फूलोदेवी नेताम ने संसद में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में आवश्यक रेल सुविधाएँ बढ़ाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने की बात कही। सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड-अमरकंटक-डिंडोरी-मंडला-धंसौर-लखनास्टैन-गोटेगांव (श्रीधाम) नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रेल मार्ग अमरकंटक-नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को गति देगा तथा इटारसी जंक्शन के माध्यम से दिल्ली एवं मुंबई जैसे महानगरों से बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करेगा। सांसद ने यह भी कहा कि बिलासपुर को CTCE Plan-2030 में शामिल करने और रायपुर-सिकंदराबाद (12771/72) एवं नागपुर-मुंबई दुरंतो (12290) का विस्तार बिलासपुर तक करने की मांग भी लम्बे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा-बीकानेर एक्सप्रेस का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। कोरबा स्टेशन-गोटेगांव पिटलाइन को तत्काल चालू करने और कोरबा-नई दिल्ली के मध्य नई सीधी ट्रेन की भी आवश्यकता है। इन लम्बित कार्यों को पूरा किया जाए तो क्षेत्र का पूरा विकास हो सकेगा।

नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर

राजनीति उचित नहीं : सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने



नक्सलवाद के मुद्दे पर चल रही सियासत को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। कांग्रेस को सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए न कि जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करना चाहिए। सीएम ने डबल इंजन सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं की बदौलत नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाया है। पिछले चार दशकों तक नक्सलवाद विकास की राह में बड़ी बाधा बना रहा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ और देश इस समस्या से मुक्त हो चुका है।

भांग के थोक दुकान लाइसेंस के लिए

आवेदन 15 अप्रैल तक आमंत्रित

रायपुर। आबकारी विभाग द्वारा भांग की थोक दुकानों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए इच्छुक आवेदक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक (अनकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में जमा करना होगा। आवेदकों का चयन 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे मैनुअल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी कारणवश तय समय पर चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो विभाग द्वारा नई तिथि घोषित कर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

ताला एनीकट निर्माण कार्य के

लिए 3.18 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा महासमुंद जिले के विकासखण्ड-पिथौरा की ताला एनीकट निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ 18 लाख 90 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के निर्माण से निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन एवं किसानों द्वारा स्वयं के साधन से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से योजना का कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कच्छर, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

जैतूसाव मठ में रामचन्द्र जी का छठी

महोत्सव मनाया गया

रायपुर। श्री जैतू साव मठ पुरानी बस्ती में भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी पर्व विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अलग अलग दिन मनाया जा रहा है और श्रद्धालुजन काफी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मंदिर समिति की ओर से जानकारी देते हुए श्री अजय तिवारी ने बताया कि वर्षों से जो परम्परा चली आ रही है हम आज भी उसे उसी स्वरूप में मनाते हैं। बुधवार को बड़े धूमधाम से श्री रामचंद्र जी का छठी महोत्सव मनाया गया जिसमें ठाकुर जी को विशेष रूप से छेवारीलड्डु, कांकेपानी, बालभोग लगाया गया। रामचंद्र जी की सेवा में मोर पंख का विशेष महत्व है इस वर्ष रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में गर्भगृह को मोर पंख से सजाया गया है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्रदेश के लिए गर्व की बात : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री से केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री रक्षा खड्गे की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से बुधवार को उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री सुश्री रक्षा निखिल खड्गे ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक श्री मयंक श्रीवास्तव एवं खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सुश्री खड्गे का शॉल, बस्तर आर्ट से निर्मित आकर्षक प्रतिकृति तथा बस्तर दुकहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित अवसर, संसाधन और सशक्त मंच उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार



खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। इन आयोजनों के जरिए

अनेक छिपी हुई प्रतिभाएँ सामने आई हैं, जिससे उ न क ा आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार द्वारा उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और अ व ष य क सु वि ध ा एं उ प ल ब्ध करारकर उनके कौशल को और निखारने

की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है और हमारे आदिवासी अंचल के युवाओं में यह नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर आज जब मुख्यधारा से जुड़ रहा है और वहां

शांति स्थापित हुई है तो निश्चित ही आने वाले समय में खेलों में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आयोजन में पारंपरिक खेल, गायन, वादन, वेशभूषा एवं व्यंजन सहित 12 विधाओं में लगभग 54 हजार प्रतिभागियों की भागीदारी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और खेल विरासत का सशक्त उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री खड्गे %खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। जगदलपुर में आयोजित इस आयोजन को उन्होंने आदिवासी सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

हर नागरिक तक त्वरित स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना हमारी प्राथमिकता : राजवाड़े

9 नवीन ‘108 संजीवनी एक्सप्रेस’ एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 9 अत्याधुनिक ‘108 संजीवनी एक्सप्रेस’ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिला चिकित्सालय सूरजपुर से शुरू की गई यह सेवा अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूरजपुर की बेटी होने के नाते यह मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं अपने जिलेवासियों को यह जीवनरक्षक सुविधा समर्पित कर रही हूँ।

उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस केवल वाहन नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली माताएँ, बहनें और बच्चों को आपातकालीन स्थिति में समय पर उपचार मिल सके और ‘गोल्डन ऑवर’ में चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस संचालन एजेंसी के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रतिक्रिया समय में निरंतर सुधार किया जाएगा। उन्होंने स्वयं इन सेवाओं की नियमित निगरानी करने की बात



कही, ताकि पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।

जिले में आवंटित 9 एम्बुलेंसों में से 2 को जिला चिकित्सालय सूरजपुर में स्थायी रूप से तैनात किया गया है, जबकि शेष एम्बुलेंसों को विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सके।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 3.80 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

प्रदेश में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जयनगर-कासापारा में 3.80 करोड़ रुपए की

प्री-पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम जारी

रायपुर। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के सम्बन्धित पालीटेक्निक कालेजों में प्रवेश के लिए प्री-पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा (पीपीटी) 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालीटेक्निक कालेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल 2026 को सायं 5 बजे तक चलेगी।

आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु 18 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 27 अप्रैल 2026 को व्यापक की वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है। परीक्षा का आयोजन 07 मई 2026 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक किया जाएगा।

यह परीक्षा राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी परीक्षा केन्द्र का चयन करने की सुविधा मिलेगी। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट vyapam-cg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

पावर कंपनीज से ईडी आलोक व एजीएम मिश्र को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज से कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री आलोक सिंह एवं अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्रा सहित कुल 8 अधिकारी-कर्मचारियों को अधिवार्धिकी पूर्ण होने पर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

पाँवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) एस. के. कटियार, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) राजेश कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन) भीम सिंह कंवर तथा निदेशक आरए पाठक ने सेवानिवृत्त ईडी सिंह एवं एजीएम मिश्र को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभव ने पाँवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति प्रदान की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों अधिकारियों ने तीनों कंपनियों में सेवाएँ देते हुए



महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आलोक सिंह अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पावर कंपनी निरंतर प्रगति कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी में किये गए नवाचार और उपायों से काफी सुधार हुआ है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की 14 वीं रिपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ए ग्रेड मिला है।

मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता से लेकर अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर कंपनीज और मुख्यमंत्री सचिवालय और गति प्रदान की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों अधिकारियों ने तीनों कंपनियों में सेवाएँ देते हुए

समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जा सके। दोनों अधिकारियों ने प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकगण वी.के. साय, सी.एल. नेताम, एम.एस. चौहान, आर.पी. नामदेव, संदीप मोदी, एम.आर. बागड़े, मनीष गुप्ता उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य अभियंता श्री ए.एम. परियल, श्री गिरिश गुप्ता, श्री के.बी. पात्रे, श्रीमती शारदा सोनवानी, श्रीमती चंद्रकला गिडवानी, श्रीमती नंदनी भट्टाचार्य, श्री अब्राहम वर्गीस, श्री संजीव सिंह, श्री संजय शुक्ला, श्री सुधाश्रम शर्मा, श्री डी. नाथ , श्री पी गोसावी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.एल.

पंचारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर में ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित समारोह में अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश

कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी श्री ऋषि कुमार ठाकुर, श्री इम्मानुएल दास, सहायक प्रबंधक श्री राधेश्याम केशरवानी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री बिशेश्वर प्रसाद कांत, कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री रामचरण वर्मा तथा लुआन सहायक श्रेणी-1 श्री महेश कुमार वर्मा को भी सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी श्री गोविंद पटेल एवं आभार प्रदर्शन अधीक्षक अभियंता श्री पंकज चौधरी ने किया। साथ ही ट्रांसमिशन कंपनी के मान संसाधन विभाग ने एजीएम (पीआर) श्री उमेश कुमार मिश्र एवं सहायक प्रबंधक श्री राधेश्याम केशरवानी को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री एएम परियल, उप महाप्रबंधक श्रीमती अल्पना शर्मा तिवारी, श्री पंकज सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मंडावी ने किया।

जग्गी हत्याकांड मामले में आज हाईकोर्ट अमित जोगी ने मांगा समय

■ आज होगी अंतिम सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खखी से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच (डीबी) में चल रही इस सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया कि अब मामले में और देरी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अगली तारीख तय करते हुए कहा कि कल इस केस में अंतिम सुनवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि साल 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में 2007 में निचली अदालत ने



28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जहां अंतिम बहस के बाद जल्द ही फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अंतिम सुनवाई से पहले बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिली है। मामले के मुख्य आरोपी रहे अमित जोगी ने रायपुर को लोवर कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी है। यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है।

लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत कार्यप्रारंभ पूजन किया।

लोक निर्माण विभाग के माध्यम से स्वीकृत इस परियोजना के तहत 3.60 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन एवं नवीनीकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए शासन द्वारा 380.15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क निर्माण पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा और सुगम संपर्क का लाभ मिलेगा।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें केवल आवागमन को सुगम नहीं बनातीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करती हैं। जयनगर से कासापारा तक बनने वाला यह मार्ग क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर श्री हरीश राजवाड़े, श्री देवधन बिंझिया, श्री अशोक अग्रवाल, श्री रितेश जायसवाल, जनपद सदस्य श्रीमती धनेश्वरी सिरदार, सरपंच श्रीमती राधा सिंह सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

संचालनालय कोष व लेखा ने शुरू कीं नई डिजिटल सेवाएं

■ वित्तीय प्रबंधन होगा और अधिक पारदर्शी व आसान

रायपुर। संचालनालय कोष एवं लेखा ने राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। इन पहलों का लक्ष्य आम नागरिकों, शासकीय विभागों एवं अन्य हितधारकों को सरल, सुलभ और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में, ई-चालान के तहत हज़ार प्रणाली को 01 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। अब सभी प्रकार की शासकीय प्रसिधियों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। नागरिक और संस्थाएँ आसानी से चालान तैयार कर राज्यसू जमा कर सकेंगे, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सहज,



समयबद्ध और पारदर्शी होगी। इसके साथ ही कोषालयों में ऑनलाइन बीटीआर सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे लेखांकन कार्यों में गति और सटीकता आएगी।

राज्य में एक केंद्रीय कोषालय का भी शुभारंभ किया गया है। इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि के भुगतान स्ह स्क्रूज़। प्रणाली के माध्यम से अब अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और केंद्रीकृत तरीके से किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया में दक्षता

सुनिश्चित होगी।

संचालनालय कोष एवं लेखा की नई वेबसाइट (सहडु.ष्.दश1.दुदु) भी लॉन्च की गई है, जहां उपयोगकर्ताओं को विभाग से संबंधित नवीनतम जानकारी, विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ और जरूरी सुविधाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। यह पहल राज्य में वित्तीय प्रशासन को आधुनिक स्वरूप देने और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल

नवविवाहित जोड़ों को प्रदान किया आशीर्वाद



रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बुधवार को कोरबा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान वे कटघोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम ढपढप-बांकीमोंगरा में आयोजित दिव्य श्री हनुमंत कथा एवं 108 दिव्यांग एवं निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से भेंट की और उनके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद

दिया। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को सम्मान स्वरूप पाँच हजार रुपये की राशि प्रदान करती है जो घोषणा भी की। कोरबा प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री डेका से कथावाचक श्री धीरेंद्र शास्त्री ने भी सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कोरबा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत सहित अन्य अधिकारी एवं आयोजन समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पांच राज्यों के चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी कसौटी

कातिलाल मांडेत

देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरल और पुडुचेरी में चुनावी गतिविधियां तेज हैं, लेकिन इस बार सबसे अधिक चर्चा कानून व्यवस्था को लेकर हो रही है। राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो पाएंगे या नहीं। सबसे अधिक विवाद और तनाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र निष्पक्ष नहीं है और मतदाताओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपों के बाद मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। यह स्थिति कानून व्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक मानी जा रही है क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल पर ही इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। राज्य में पहले भी चुनावों के दौरान हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस बार भी पूरक मतदाता सूची को लेकर असमंजस और लाखों नामों पर विचाराधीन स्थिति ने प्रशासनिक चुनौती को और बढ़ा दिया है। स्पष्ट है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसे संभालना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं जा सकती। यहां कांग्रेस और एआईयूडीएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना सामने आई है, जिसने चुनावी माहौल में तनाव का संकेत दिया है। यह घटना दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कभी-कभी टकराव का रूप ले लेती है। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन भारत के ही केरल में चुनावी प्रक्रिया एक अलग ही स्वरूप में नजर आती है। यहां प्रत्यक्ष हिंसा की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, फिर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक टकराव लगातार जारी रहता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य अपेक्षाकृत संतुलित नजर आता है, लेकिन प्रशासन को पूरी सतर्कता बनाए रखनी होती है। पुडुचेरी में चुनावी गतिविधियां सीमित दायरे में होती हैं, लेकिन यहां भी राजनीतिक समीकरण काफी जटिल होते हैं। छोटे क्षेत्रफल के बावजूद यहां गठबंधन राजनीति का प्रभाव अधिक है। हालांकि अब तक यहां से किसी बड़ी हिंसक घटना की सूचना नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए सावधानी आवश्यक है। इन पांचों राज्यों की स्थिति का समग्र विश्लेषण यह बताता है कि जहां एक ओर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

काई भी बालिश इसका यह अर्थ लगा सकता है कि जब वेद में एक व्यक्ति को जार मानते और कहते हुये भी विधिवत् पूजा जाता है तब इस प्रकार का दुराचार करने पर मैं ही प्रफ़ुन्य क्यों हूँगा। परन्तु पौराणिक-स्वरूप को साधना पढ़कर या सुनकर एक मूर्ख से मूर्ख भी ऐसे दुराचार में प्रवृत्त होने का साहस न कर सकेगा, क्योंकि इसके पढ़ने से तो पाठकवर्ग के हृदय पर यही प्रभाव पड़ेगा कि जब देवराज इन्द्र को भी इस तरह की चेष्टा करने पर दण्डभागी होना पड़ा तब मैं तो किस खेत की मूली हूँ? अतः इस अकार्य से भरसक बचना चाहिये ।

कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ वेद, इन्द्र को जार बताते हुये भी दोषी को गोद में छिपाये रखने की सी नीति को बर्तता हुआ, दीख पड़ता है, वहां पुराण मानव-मर्यादा की रक्षा के लिये दोषी व्यक्ति को पदाधिकार की लिहाज छोड़कर उचित दण्ड दिलाते

का पक्षपाती जान पड़ता है। इसलिये इस आख्यान से पुराणों पर जितना दोषारोपण किया जा सकता है उससे कहीं अधिक वेदों पर भी आ पड़ेगा ! वैदिकता का स्वांग भरने वाले समाजी भाइयों को खूब सोच समझकर ऐसे आक्षेप करने चाहियें।

कदाचित् जिज्ञासा भाव से कोई सज्जन यह पूछना चाहें कि-निस्सन्देह् दयानन्दी समाज को केवल पुराणों पर आक्षेप करने का कुछ भी अधिकार नहीं है क्योंकि वेदों और पुराणों दोनों में ही यह कथा समान रूप से वर्णित है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से देवराज इन्द्र का यह अकार्य निन्दनीय अवश्य है. इसका क्या उत्तर है? हम अपने जिज्ञासु महोदय को बतलाएंगे कि सुनिये- प्रथम तो इन्द्र, देवयौनि का महापुरुष है। वेदादि शास्त्रों में देवयौनि को भोगयौनि माना है, जैसा कि हम वेद-पुराण-समन्वयाध्याय के देवतावाद प्रष्ट् में सप्रमाण एवं सयौक्तिक सिद्ध कर आए हैं।

क़्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

मोदी पर त्यक्तिगत प्रहार टिकेगा नहीं!

विक्रम उपाध्याय

जब पूरी दुनिया अपने अस्तित्व पर चुनौती महसूस कर बचाव के लिए संघर्ष करने में लगी है, तो भारत में अस्तित्वहीन पड़ा विपक्ष अपने लिए इस संकट की घड़ी को सत्ता में लौटने का एक अवसर मान रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग में जब हर देश में राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष एक टेबल पर बैठ कर चुनौतियों से पार पाने का दम भर रहा है, तो भारत में विपक्ष और विरोधियों की ओर से सरकार के मुखिया पर सबसे भीषण प्रहार किया जा रहा है, केवल नीतिगत ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी, प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा और विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

एक तरफ उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री ठहराने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के व्यक्तित्व और आचरण को ही तार तार करने का षड्यंत्र रचा रहा है। वैसे ही जैसे 2013 में कोबरापोस्ट और गुलेल द्वारा किसी नारी की निजता भंग करने के आरोप के सहारे मोदी को छवि बिगाड़ने का एक प्रयास किया गया था।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिना विचलित हुए ईरान और अरब दोनों के साथ अद्भुत सामंजस्य बिठाते हुए, केवल भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा संरक्षता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। विपक्ष के कुछ बड़े नेता पहले भी कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ निजता भंग करने के आरोप लगाते रहे हैं।

उनमें ही एक आरोप प्रयास पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल के जरिए जासूसी करने का भी रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर वहाँ विरोधियों की दाल नहीं गली, और वे सर्वोच्च न्यायालय से झटका खा कर लौट आए। वर्तमान सरकार के मुखिया विपक्ष के नेताओं से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह बात आम लोगों को भी हास्यास्पद लगी।

विपक्ष में इस समय कोई ऐसा नेता नहीं है, जो पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि पर दाग लगाने और जनता में उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने का माहा रखता है। कारण केवल यह नहीं कि विपक्ष के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है एक राजनीतिज्ञ के नाते नरेंद्र मोदी



द्वारा स्थापित अपने सार्वजनिक जीवन के मानदंड पर उंगली उठा सके, बल्कि मोदी की जीवन शैली ऐसी रही है, कि वहाँ किसी तरह कि कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बनती है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता की राजनीति के नायक बने तब उम्र की 50 वीं दहलीज पार कर चुके थे। उसके पहले वे या तो संघ के काम में देश भर के संघ कार्यालयों में रहे या फिर बीजेपी की व्यवस्था में। निजी जिंदगी और निजता के संरक्षण का कोई विकल्प भी अपने लिए नहीं चुना।

मीडिया में भी सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़कर किसी और राजनीतिज्ञ ने उनके किसी महिला के साथ संबंध को लेकर कभी टिप्पणी नहीं की। स्वामी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कई ऐसी टिप्पणियां की है और इसके कारण ही उन्होंने एक गंभीर राजनेता की पहचान खो दी है। नरेंद्र मोदी लगभग 25 वर्षों से विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।

काम के मामले में कोई उन्हें चुनौती दे नहीं पा रहा है। राजनीति के मैदान में वे विपक्ष की पकड़ से बहुत आगे निकल गए हैं। इसीलिए विरोधी राजनतिक पार्टियां जनता में मोदी के प्रति बनी धारणा को ही कमजोर करने की ज़रूरत सिद्दत के साथ महसूस कर रही हैं। कांग्रेस का नेतृत्व चुनावी मुकाबले में कमजोर और अक्षम सिद्ध हो चुका है।

प्रधान मंत्री के साथ विकास के मुद्दे पर काँग्रेस बहस से भी बचती है। जनता से किये हर वादे पर भी पीएम मोदी खरे उतरते हैं। हर

भारतीय को मोदी सरकार के कारण अपने अपने जीवन में कोई ठोस सुधार दिखाई देता है। 12 साल के केंद्र में शासन में किसी भ्रष्टाचार या घोटाला का नाम तक नहीं आया। इसलिए ही मोदी की व्यक्तिगत छवि पर लगातार हमले की रणनीति पर विपक्ष अब काम कर रहा है।

मोदी के जीवन के कुछ पहलुओं को बुरा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ताकि लोगों के मन में कुछ सवाल पैदा कर सके। पर वे शाायद भूल

रहे हैं कि उनके इस बचकाने रवैये से उनकी थोड़ी-बहुत साख जो बची है उसे भी गँवा बैठेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने देश विदेश के अपने सलाहकारों से मंत्रणा करने के बाद शायद यह तय कर लिया है कि पीएम मोदी को कमजोर करने के लिए एंटी परसेप्शन मैनेजमेंट पर ही सारा जोर देना होगा और सोशल मीडिया के जरिए उनकी व्यक्तिगत छवि पर आघात करना होगा।

काँग्रेस के लिए यह रणनीति कितना काम करेगी यह तो आने वाला ही समय बताएगा, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं के बीच इस मुकाबले को ले जाने की चुनौती बहुत बड़ी होगी। पीएम मोदी ने ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देने के मामले में कांग्रेस से बहुत ज्यादा बेहतरी तरीके से काम किया है और पीएम मोदी की लोकप्रियता इसी से सबसे ज्यादा स्थापित भी हुई है।

वहाँ बीजेपी की छवि धूमिल करना काँग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। काँग्रेस के अपने पास मोदी पर व्यक्तिगत लांछन लगाने वाले विश्वसनीय चेहरे भी नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति काँग्रेसी नेताओं के दुर्व्यवहार और जहरीले बोल की एक लंबी फेहरिस्त है। पीछे की छोड़िए वर्तमान के ही कई काँग्रेसी नेता महिलाओं के मान मर्दन के आरोपी हैं।

नाम लीजिए राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला का, उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के राजनीतिक योगदान पर अभद्र

श्री हनुमान जन्मोत्सव



अंजनी पुत्र, केसरीनन्दन और पवनपुत्र कहलाते हैं, कलियुग के देवता तथा चिरंजीवी माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के पंचमीय क्षे्र में हुआ माना जाता है। इस पावन व पवित्र दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। हनुमान भक्त व्रत रखते हैं और बालाजी महाराज को चूरमा, लड्डू, पेड़ा, नारियल, लाल ध्वज व सिंदूर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना से भय, संकट, रोग, भूत-प्रेत बाधा और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी

है- अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवानकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नाममि॥

वे अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाय्य, ईशित्व और वशित्व सहित अष्ट सिद्धियों के स्वामी तथा पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक नव निधियों के दाता कहे जाते हैं और इसीलिए उन्हें कहा गया है- अष्ट सिद्धि नव निधि के दाताच। उनके बल का अलंकारिक वर्णन यह है कि 10 हजार हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, 10 हजार ऐरावतों का बल एक इन्द्र में और 10 हजार इन्द्रों(भगवान् इंद्र) का बल उनके(हनुमान जी) एक रोम में निहित है। वे इच्छानुसार सूक्ष्म से विशाल रूप धारण कर सकते हैं; लंका में प्रवेश करते समय

टिप्पणी की थी। नाम लीजिए काँग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का उन्होंने 2024 के आम चुनाव के दौरान हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का भाव पूछ लिया था। कर्नाटक के एक काँग्रेसी नेता ने महिलाओं को घर पर खाना बनाने तक ही रखने की सलाह दे डाली थी।

बंगाल के वरिष्ठ काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बख्शा, उन्हें राष्ट्रपती बना डाला। काँग्रेस की एक पूर्व नेता, चेरियन फिलिप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि काँग्रेस पार्टी के टिकट यौन लाभ के बदले भी दिए जाते थे। अब मधु किश्र्व द्वारा सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बारे में एक सनसनी रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने पर विपक्ष के नेता फूले नहीं समा रहे हैं।

काँग्रेस महिला मोर्चा की नेता अलका लांबा हों या तृणमूल काँग्रेस की मोईया मित्रा सबने अपने अपने तरीके से पीएम मोदी के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि मधु किश्र्व पहले भी कई गलत या भ्रामक पोस्ट कर चुकी हैं। जाहिर है काँग्रेस का उद्देश्य बिना किसी पूर्ण शोध के जंगल की आग की तरह भ्रम फैलाना है।

काँग्रेस पहले भी ब्लैक लाइव्स मैटर की तरह देश में जाति आधारित आंदोलन को, काले कानून के नाम पर किसानों के आंदोलन को और कोविड के दौरान एंटी-लॉकडाउन प्रोटेस्ट को हवा देकर पीएम मोदी को कमजोर करने की असफल कोशिश कर चुकी है। दुनिया पीएम मोदी के अनुशासन की कायल है।

उनके बारे में यह लोगों को पता है कि वे शायद अकेले नेता हैं जो खरी-खरी कहने और किसी की भी अक्षमता पर उसका आलोचना करने से नहीं हिचकते। उनका सीधा सिद्धांत है – काम करो नहीं तो बाहर निकलो। वे समय के बहुत पाबंद और बहुत व्यवस्थित नेता हैं। उनमें औरों की तरह अमीर बनने का जुनून नहीं है।

वह मीडिया को भी खुश करने की कोशिश नहीं करते। वह बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। उनके करीबी साथियों की भी संख्या कम है। इसलिए उनकी राजद्वार भी कम है। उनकी माँ के अलावा उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार को प्रधानमंत्री आवास में नहीं देखा गया, इसलिए मोदी पर व्यक्तिगत लांछन लगाना और उसे सिद्ध करना संभव नहीं है।

युद्ध ने खड़ा कर दिया है बहुत बड़ा मानवीय संकट

नीरज कुमार दुवे

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को एक गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। बीते एक महीने से लगातार हो रही बमबारी ने न केवल हजारों लोगों की जान ली है, बल्कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 1937 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चौबीस हजार आठ सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े इस बात की गंभीरता को दर्शाते हैं कि यह संघर्ष अब व्यापक मानवीय आपदा बन चुका है।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक, इस संघर्ष के कारण अब तक बत्तीस लाख से अधिक लोग ईरान के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। तेहरान, इस्फहान और केरमानशाह जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा हवाई और ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके चलते लोग इन इलाकों को छोड़कर अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों और कैस्पियन सागर के पास के उत्तरी इलाकों की ओर जा रहे हैं। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षित स्थान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कई जगहों पर लगातार हमलों के कारण लोगों के सामने यह दुविधा है कि वे अपने घरों में रहें या पलायन का जोखिम उठाएं।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, यह संकट अब ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैल चुका है। 19 मार्च तक अस्सी हजार से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां सतर हजार से अधिक लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा पाकिस्तान, अजरबैजान, इराक और तुर्कमेनिस्तान में भी हजारों लोग पहुंचे हैं। यह पलायन इस बात का संकेत है कि लोगों को अब अपने देश में जीवन सुरक्षित नहीं लग रहा। डर, असुरक्षा और लगातार हो रहे हमलों ने आम नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए



मजबूर कर दिया है।

वहीं सीमाओं पर हालात और भी ज्यादा कठिन होते जा रहे हैं। ईरान से भागकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचने वाले लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहत एजेंसियों के अनुसार, सीमाई चौकियों पर भारी भीड़, लंबी कतारें और सीमित संसाधनों के कारण लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है।

इसके अलावा, सुरक्षा स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार झड़पें और गोलाबारी हो रही है, जिससे शरण लेने आए लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। हाल के दिनों में सीमा क्षेत्रों में तोपखाने हमलों और सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जिनमें आम नागरिक भी घायल हुए हैं। साथ ही कई बार सीमाएं अचानक बंद कर दी जाती हैं या सीमित समय के लिए खोली जाती हैं, जिससे हजारों लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों को जबर्न वापस लौटाया जा रहा है, जबकि कई परिवार बिछड़ जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग एक युद्ध से बचकर भाग

का समर्थन भी किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि देश के भीतर असंतोष कितना गहरा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 47 वर्षों का दर्द अब असहनीय हो चुका है। वहीं एक अन्य व्यक्ति, जो सात साल जेल में रहा, उसने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने झेली है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। हालांकि, लोग डर और उम्मीद दोनों के बीच जी रहे हैं। वह अपनी जान और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि यह संघर्ष किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाए।

वहीं ईरान में रहने वाले चालीस लाख से अधिक अफगान शरणार्थी इस संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें से अधिकतर शहरों में रहते हैं, जो हमलों का मुख्य लक्ष्य बने हुए हैं। इनमें से कई लोगों की आजीविका खत्म हो चुकी है और उनके पास न तो सुरक्षित स्थान है और न ही देश छोड़ने की अनुमति है। बताया जा रहा है कि करीब पैंतीस हजार अफगान पहले ही वापस अपने देश लौट चुके हैं, जबकि दस लाख से अधिक लोगों पर जबर्न वापसी का खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि अफगानिस्तान खुद संकट से जूझ रहा है।

दूसरी ओर, ईरान के शहरों से आ रही तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। कई इलाकों में घर, अस्पताल और स्कूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तेहरान के लगभग हर इलाके में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लोग अपने घरों की खिड़कियों पर टेप लगा रहे हैं ताकि कांच टूटने से होने वाली चोटों से बचा जा सके। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और बैंकिंग व्यवस्था भी प्रभावित है, जिससे आम जीवन और कठिन हो गया है। लोग रातभर बम धमाकों की आवाज सुनते हुए डर के साये में जी रहे हैं।

उधर, मानवीय संगठनों का कहना है कि राहत कार्यों के लिए जरूरी धन की भारी कमी है। हर सप्ताह अरबों रुपये युद्ध पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में करीब अठ्ठाइस लाख लोगों की मदद के लिए 80 मिलियन डॉलर की जरूरत है, जबकि अफगानिस्तान में 17.5 मिलियन लोगों के लिए 1.71 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। लेकिन अब तक इसका बहुत छोटा हिस्सा ही उपलब्ध हो पाया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह युद्ध जारी रहा तो यह एक और बड़े मानवीय संकट का रूप ले सकता है। लाखों लोग सीमाओं के पार जाने को मजबूर होंगे, जिससे पहले से दबाव झेल रहे देशों पर और बोझ बढ़ेगा। देखा जाये तो यह संघर्ष आम लोगों को ऐसी पीड़ा दे रहा है जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है कि सभी पक्ष नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकें और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

बहरहाल, ईरान और अमेरिका के बीच यह युद्ध अब पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। हजारों मौतें, लाखों विस्थापित लोग और बर्बाद होती जिंदगी इस बात का संकेत हैं कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

आज का इतिहास

- १९११ ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो ने देश की पहली राष्ट्रीय जनगणना की।
- १९१२ टाइटेनिक जहाज का समुद्री परीक्षण की शुरुआत हुई।
- १९३५ ग्रेट ब्रिटेन के रॉबर्ट वॉटसन-वाट ने पहली व्यावहारिक रडार प्रणाली का तैयार किया।
- १९४० ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- १९४१ जर्मन और इतालवी सेना ने अंग्रेजों को अजदबिया शहर से बाहर का रास्ता दिखाया।
- १९४२ काँग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया।
- १९७३ १९६७ में ओहियो स्टेट बार द्वारा आयोजित एक प्रयोग की निरंतरता के आधार पर लेक्सिस कंप्यूटर-सहायक कानूनी अनुसंधान सेवा शुरू की गई।
- १९७३ लिबरल मूवमेंट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लिबरल और कंट्रीलेग से अलग हो गया।
- १९८२ अर्जेंटीना के विशेष बलों ने फ़ॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया, जिससे फ़ॉकलैंड युद्ध छिड़ गया।
- १९८९ फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति निर्वाचित।
- १९९५ गाजा में एक विस्फोट में ८ लोग मारे गए, जिसमें हमาส के नेता भी शामिल थे।
- १९९८ मिनेसोटा में विश्व पुरुष फिगर स्केटिंग चैंपियन आयोजित किया गया था।
- २००१ नेपाल में माओवादी विद्रोहियों द्वारा ३५ पुलिस अधिकारियों की हत्या।
- २००१ मेट्रोडोम मिनियापोलिस में ६३ वें एनसीएफ पुरुषों की बेसबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी।
- २००६ मध्य अमेरिका में ६० से अधिक बवंडर छू गए, जिससे २७ लोगों की मौत हो गई और लगभग १.१ बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
- २००७ सोलोमन द्वीप में शक्तिशाली सुनामी आयी।
- २००९ डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री आंदे फोग रासमुसेन को १ नाटो शिखर सम्मेलन में नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
- २०१० ब्राजील के भूमि सुधार कार्यकर्ता पेड्रा अलकंतरा डी सुज़ा को दो लोगों ने उनके सिर पर पांच बार गोली मारी, जबकि उन्होंने अपनी साइकिल सराय पारा की सवारी करने की कोशिश की।
- २०११ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोगों द्वारा प्रो और कार्बन विरोधी कर रैलियों में भाग लिया गया।

बाब अल-मंदब बंद हुआ तब तो मंदी छा जाएगी

अभिनय आकाश

साल 1987 का दौर जब ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे। उस दौरान वो ईरान पर हमले की बात करते बुरे आए। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान पर हमला करके उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना चाहिए। जब इंटरव्यू कर रही महिला पत्रकार उनसे पूछती हैं कि आप ये करेंगे कैसे? क्या सीधा हमला होगा? इस पर ट्रंप कहते हैं हां हमला होगा। मिडिल ईस्ट में एक जंग छिड़ेगी और अमेरिका को ना केवल ईरान के ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना है बल्कि उस कब्जे को बनाकर भी रखना है ताकि उससे वसूली किया जा सके। उस नुकसान की वसूली जो ईरान ने अमेरिका का किया। यानी इससे साफ होता है कि ट्रंप के दिल में ईरान पर चढ़ाई का विचार हमेशा से था। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो जैसा पैसा आने पर आदमी बचपन के सपने पूरे करने की कोशिश करता है। गैर जरूरी चीजें भी खरीदता है कि बचपन में नहीं ले पाया अब खरीदूंगा पैसा है। वैसे ही ट्रंप भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अब पावर है।

ट्रंप की दिक्रतें भी बढ़ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा कोई साथ आ नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप से पूछेंगे कि ऑब्लिविउ क्या है? कारण जाने बिना ऑस्ट्रेलिया हाथ नहीं जलाना चाहता।

यही काम नेटो ने भी ट्रंप के साथ किया है। सीधे मना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। लेकिन वो भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। तो एक तरफ ट्रंप की टीम में कोई आ नहीं रहा और दूसरी तरफ ईरान की टीम में उस खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है जिसका ईरान को इंतजार था। 29 मार्च को यमन की हूती सरकार जंग में शरीक हो गई। उसने इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। 29 मार्च को इस सरकार के प्रवक्ता याया हरी ने जंग में आधिकारिक तौर पर शामिल होने की घोषणा की। यह भी बताया कि उन्होंने इजराइल पर रूजुज मिसाइल से हमला किया है और आने वाले दिनों में हमले जारी रहेंगे।

हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय जूदी के हथियारबंद लड़ाके का एक गुट है। 1990 में यह गुट बना था। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद वहां की सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से यमन में गृह युद्ध जारी है। आज के समय में यमन के बड़े हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इसमें मुख्य तौर पर पश्चिमी इलाके हैं। इन हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान इनके जरिए यमन में प्रॉक्सी वॉर भी लड़ता आया है। ईरान ने हूती विद्रोहियों की तरह पूरे पश्चिमी एशिया में ऐसे घुटों का एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इसे एक्सेस ऑफ रेंजिस्टेंस कहा जाता



है। हूतियों के अलावा फिलिस्तीन का हम्मास और लेबनान का हिजबुल्ला इसमें शामिल है। ईरान की तरह ही इन तीनों गुटों का मुख्य दुश्मन इजराइल और अमेरिका है। अब इस वक्त इजराइल ने ईरान के साथ लिबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ भी जंग झेल रखी है। लगातार उसके ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हम्मास के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें हम्मास की लगभग पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा चुका है। गजा में उसके नेटवर्क को तबाह कर दिया गया था। इस दौरान इसराइल ने हूतियों को भी नुकसान पहुंचाया। उनके प्रधानमंत्री से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ तक को खत्म कर दिया गया। लेकिन इजराइल हूतियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अलतूती को अब तक ढूंढ नहीं पाया है।

ईरान अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में अब तक हूती नहीं उतरे थे।

चुनावी मौसम में मुफ्त बांटने की होड़

पवन

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा की जो होड़ दिख रही है, वह लोकतंत्र में आधी आबादी के महत्व को तो रेखांकित करती है, लेकिन मुफ्त रेवड़ी बांटने की व्यापक होती संस्कृति की ओर भी इशारा करती है, जो लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिहाज से चिंताजनक है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और असम में महिला मतदाताओं की संख्या निर्णायक बनी हुई है, जबकि, तमिलनाडु, केरल व पुदुचेरी में तो महिला मतदाताओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ा हुआ है। जाहिर है कि इन राज्यों में सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है और राजनीतिक दल इसे भली-भांति समझते भी हैं। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार और अन्नाद्रमुक में महिला मतदाताओं के लिए किए जा रहे वादों की होड़ हो, या फिर असम सरकार का बिहू समारोह के लिए महिलाओं को चार-चार हजार रुपये देने का एलान। केरल सरकार की स्त्री सुखम योजना था, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना, जिसकी राशि में हाल ही में बढ़ोतरी की गई है या फिर पुदुचेरी में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने का वादा।

इन सभी योजनाओं में हालांकि 'मुफ्त' जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2023 का सर्वे भी कहता है कि महिलाएं अवैतनिक श्रम के जरिये देश के जीडीपी में करीब सात फीसदी का योगदान देती हैं। लेकिन, ये सभी योजनाएं जिस विचार पर टिकी हैं, उसके



साथ दिक्रत यह है कि यह महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा को दरकिनार कर उन्हें महज लाभार्थी बना देता है। हमारे समाज में जहां लंबे समय तक महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा गया हो, वहां उन्हें विशेष सहायता देना एक आवश्यक नीतिगत उपाय हो सकता है। उज्ज्वला, जनधन खाते, मातृत्व लाभ योजनाएं इत्यादि ने साबित किया है कि सही दिशा में दी गई सहायता महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव ला सकती है। लेकिन, चुनावी मौसम में मुफ्त रेवड़ी बांटने की यह प्रतिस्पर्धा नीतिगत गंभीरता कम और राजनीतिक दलों की सियासी फायदा उठाने की मंशा को ही अधिक दिखाती है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी संसाधनों को मुफ्त बांटना और जन कल्याणकारी योजनाओं में इनका निवेश करना दो भिन्न बातें हैं, और इस भिन्नता का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक दल वाकई महिलाओं का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो उन्हें लुभावने वादों से आगे बढ़कर ठोस व दृढ़दर्शी नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी, सिर्फ तभी महिला सशक्तीकरण एक नारा नहीं, बल्कि वास्तविकता बन सकेगा।

केरल के चुनाव सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण

कल्याणी शंकर

विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। सत्तारूढ़ सी.पी.आई. (एम) (माकपा) निर्यंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयासों को तेज कर रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यू.डी.एफ. सत्ता की तलाश में है, जिसे पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों के मजबूत परिणामों से बल मिला है। आगामी चुनाव एल.डी.एफ. की सत्ता बरकरार रखने की क्षमता और यू.डी.एफ. की कड़ी चुनौती का परीक्षण करेंगे। 1982 के बाद से, मतदाताओं ने हर 5 साल में बारी-बारी से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एल.डी.एफ.) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यू.डी.एफ.) का समर्थन किया है, जिससे किसी भी सरकार को लंबे समय तक सत्ता में रहने से रोका जा सका। हालांकि, 2021 में मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व में एल.डी.एफ. ने लगातार दूसरा कार्यकाल जीता। दोनों पार्टियां वर्तमान में मोदी सरकार का विरोध और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। एन.डी.ए. केरल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ाने और महत्वपूर्ण सीटों जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य स्तर पर कांग्रेस के अधिकारी आश्चर्य महसूस करते हैं। हालांकि, स्थानीय स्तर पर गंभीर समस्याएं हैं, जो भविष्य के चुनावों में उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा प्रमुख राजनीतिक गठबंधन है, जिसे मुख्य रूप से हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है। इसके विपरीत, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा अल्पसंख्यक समूहों के समर्थन पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उध्द ने यू.डी.एफ. से कुछ जितने वोटों को अपनी ओर खींचा है, जिसमें इंडियन यूनिजन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम.एल.) और केरल कांग्रेस शामिल हैं, जो लगभग 27 प्रतिशत मुस्लिमों और 18 प्रतिशत ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल के 6 जिलों में कम से कम दस 'सिंवा' (अनिश्चित) निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनावों में, तीनों गठबंधनों को मतदाताओं का लगभग समान समर्थन मिला था। कांग्रेस के भीतर आंतरिक संघर्ष, विशेष रूप से उम्मीदवारों के चयन को लेकर, पार्टी की एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हैं। भले ही सतीशन, चेन्नियला और



वेणुगोपाल जैसे नेता विधानसभा चुनावों से पहले एकजुट दिख रहे हों लेकिन वे अभी भी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में, भाजपा ईसाई मतदाताओं, विशेष रूप से मध्य केरल में, के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने, प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने प्रयासों में वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य खुद को पारंपरिक यू.डी.एफ. गठबंधन के एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना है। पार्टी बुनियादी ढांचे, नैकरियों और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन (एन.डी.ए.) ने स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि केरल का राजनीतिक परिदृश्य, जिस पर यू.डी.एफ. और एल.डी.एफ. का दबदबा रहा है, बदल सकता है।

उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस के भीतर मतभेद, जिसमें टिकट वितरण के बारे में राहुल गांधी की चिंताएं भी शामिल हैं, पार्टी की एकजुटता को कमजोर और मतदाताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्तावित सूची में लगभग 60 प्रतिशत उम्मीदवार लोकसभा सदस्य और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से जुड़े हैं। गांधी ने कांग्रेस के भीतर अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। चुनाव समिति केवल राज्य इकाई के नामांकन पर निर्भर रहने की बजाय जाति समीकरण, जीतने की क्षमता और पिछले चुनावी परिणामों जैसे प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार सूची में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर भी चिंतित हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति स्पष्ट है। माकपा ने प्रभावी प्रचार

अभिनय आकाश

किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी शिक्षा व्यवस्था में बसती है। और जब कोई युवा नेतृत्व उस आत्मा को राजनीति के चंगुल से छुड़ाने का संकल्प ले ले तो इतिहास रचा जाता है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री बालन शाह ने सत्ता संभालते ही वह कर दिखाया जिसकी हिममत दशकों से कोई नहीं कर पाया। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले संगठनों को 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। विदेशी नामों वाली मैकाले पद्धति पर प्रहार हुआ है और बचपन को परीक्षा के बोझ से आजाद कर दिया गया है। क्या है बालेन का यह 100 दिवसीय एक्शन प्लान जिसको लेकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध। 60 दिन में दफ्तर खाली करने के आदेश। अब विदेशी षड्यंत्र का शिक्षा से खात्मा। ऑक्सफोर्ड सेंट जेवियर्स को बदलने होंगे नाम। अब नेपाल में होगा परीक्षा मुक्त बचपन। कक्षा पांच तक कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उठी क्रांति की लहर अब पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने 100 दिवसीय एक्शन प्लान के जरिए शिक्षा के उस पुराने ढांचे पर प्रहार किया जो दशकों से राजनीति के दौमक का शिकार थी। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला है छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध। अब नेपाल की स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किसी भी राजनीतिक दल के झंडे नहीं दिखेंगे।

बालेन कैबिनेट ने साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र होंगे। नेताओं के अखाड़े नहीं। आगले 60 दिनों के भीतर सभी राजनीतिक संगठनों को कैंपस से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। दलगत राजनीति की जगह वॉइस ऑफ स्टूडेंट का उदय। अगले 90 दिनों में



बनेगा गैर राजनीतिक लोकतांत्रिक तंत्र। छात्रों की वास्तविक समस्याओं का होगा समाधान। प्रोपेगंडा का नहीं। शिक्षा के कैलेंडर को राजनीति के कारण नहीं रुकने दिया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि छात्र राजनीति के नाम पर युवा किसी एक विचारधारा के पीछे आंख मूंद कर चल देते हैं। बालन शाह का मानना है कि इससे मौलिक चिंतन और शोध की क्षमता मर जाती है। जेएनयू और डीयू जैसे संस्थानों में जो गंध मची है नेपाल उससे बचना चाहता है। बालेन ने विकल्प दिया स्टूडेंट कार्सिल। यह कोई राजनीतिक विंग नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला एक पारदर्शी मंच होगा। इसका मकसद है छात्रों को फॉलोअर्स बनाने की बजाय सीकर यानी कि खोजी बनाना। जब छात्र किसी पूर्वगृह से मुक्त होकर चिंतन करेगा तभी वह समाज को कुछ नया दे पाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों और कॉलेजों के नाम विदेशी हैं। उन्हें इसी साल के भीतर नाम बदलने होंगे और नेपाली नाम रखना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता अनिवार्य नहीं होगी।

नेपाल सरकार ने मनी लॉन्डिंग मामले में तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों (देउवा, ओली और प्रचंड) समेत दो मंत्री और उनके परिवार की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। वहीं, केपी ओली और गृह लेखाक की हिरासत पर मंत्री

तेज हो रही है महिला वोटरों को लुभाने की होड़

प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता के दावेदारों में महिला वोटरों को लुभाने की होड़ मची है। इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनको चुनौती देने वाले दल भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। भाजपा इन राज्यों में अलग-अलग भूमिकाओं में है। बंगाल में वह जहां इस बात सत्ता में आने का सपना देख रही है वहीं असम में उसका जोर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। इन दोनों राज्यों में समानता यह है कि यहां महिला वोटरों की तादाद कुल वोटरों का करीब 50 फीसदी है और चुनावी नतीजे तय करने में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। बिहार में बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खते में 10-10 की रकम भेजने के फैसले ने एनडीए की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह असम सरकार ने भी चुनाव से ठीक पहले राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं के खते में तीन हजार छह सौ करोड़ रुपए भेजे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अल्पसंख्यकों के साथ ही महिलाओं की भी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। राज्य में कम से कम दो दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। इन महिला वोटरों ने ही वर्ष 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने में ममता बनर्जी की मदद की थी। वर्ष 2021 के नतीजों से साफ है कि उस समय तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं के 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे जबकि भाजपा के मामले में यह आंकड़ा 37 फीसदी था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए लगातार तमाम योजनाएं शुरू करती रही हैं। इनमें लक्ष्मी भंडार सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इसके तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम में पांच-पांच सौ रुपए की वृद्धि कर दी है। शुरुआत में इसके तहत हर महीने पांच सौ रुपए दिए जाते थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता ने ठीक रकम पांच सौ रुपए बढ़ा दी थी और यह चुनाव से यह पहलू इसमें सौ रुपए पांच सौ रुपए जोड़ दिए गए हैं। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 15 सौ और अनुसूचित जाति व जनजाति तबके की महिलाओं को 17 सौ मिल रहे हैं। वर्ष 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन के बाद सरकार ने महिलाओं के हित में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं शुरू की थी। इनके तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक



सहायता दी जाती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि पार्टी को इन कल्याण योजनाओं का फायदा मिला है। लेकिन उनकी दलील है कि पार्टी का मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरी ओर, भाजपा भले तृणमूल पर महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाती हो, इन वोटरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही उसने सत्ता में आने की स्थिति में लक्ष्मी भंडार की जगह अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने तीन हजार रुपए देने का वादा किया है। बंगाल में भी महिला वोटरों की संख्या लगभग पुरुष वोटरों की बराबर है। खासकर इस राज्य में महिलाएं पुरुषों, के मुकाबले ज्यादा मतदान करती रही हैं। असम में भी सत्तारूढ़ भाजपा महिलाओं की कल्याण योजनाओं के बूते तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है। चुनाव के एलान से ठीक पहले अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के खते में 3600 करोड़ की रकम भेजी गई। इसके अलावा स्वनिर्भर नारी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एकमुश्त 10 हजार रुपए की सरकारी सहायता दी जाती है। असम में महिला वोटरों की तादाद 1 20 करोड़ है। भाजपा को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस ने भी सत्ता में आने की स्थिति में राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने बिना शर्त रकम भेजने के साथ ही अपना करोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने की इच्छुक महिलाओं को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल और असम में महिलाएं राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। भले ही कई तमाम राजनीतिक दल उनको टिकट देने में कंजूसी बरते, लेकिन उनके वोट सबके लिए अहम हैं। यही वजह है कि उनको लुभाने की होड़ लगातार तेज हो रही है। खासकर ननदीकी मुकाबले वाली सीटों में महिलाओं के एक या दो फीसदी वोट नतीजे बदल सकते हैं।

अप्रैल माह में होंगे 4 बड़े ग्रह गोचर

अप्रैल महीने से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर और धार्मिक लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत खास महत्व का होता है। सनातन धर्म में इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च-अप्रैल के महीने में ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होता है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि ग्रह गोचर के लिहाज से अप्रैल का महीना बड़ा ही खास माना जा रहा है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये चार बड़े ग्रह अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल का गोचर मीन राशि में होगा। इसके बाद बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में होगा। 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर कर जाएंगे। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति मीन राशि में होगी। शनि और सूर्य पहले से ही मीन राशि में मौजूद हैं। वहीं, इस महीने शुक्र का गोचर भी स्वराशि वृषभ में होगा। शुक्र के स्वराशि वृषभ में गोचर करने से मालव्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में मालव्य राजयोग को प्रभावशाली और शक्तिशाली राजयोग माना गया है।

2 अप्रैल 2026 को मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। जिससे भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां वह उच्च के माने जाते हैं। वहीं 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो सुख-सुविधाओं, प्रेम और भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देता है।

वहीं महीने के अंत में 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। ऐसे में ग्रहों के इस महत्व-पूर्ण बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा।

2 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में गोचर
अप्रैल माह में पृथ्वी पुत्र और युद्ध के देवता मंगल गुरु ग्रह की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 02 अप्रैल को मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पर पहले से शनिदेव विराजमान हैं जिसके कारण मीन राशि में शनि-मंगल की युति बनेगी। मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का स्वामित्व होता है। वहीं ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफलदाता और मंगल को युद्ध, साहस, पराक्रम और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शनि और मंगल दोनों की ही गिनती पाप ग्रहों में होती है और दोनों का एक ही राशि में आने से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति से कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे कुछ राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिल सकता है।

11 अप्रैल को बुध का मीन राशि में गोचर
बुध 11 अप्रैल 2026 को मेष राशि की यात्रा को विराम देते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध के राशि परिवर्तन से लोगों में रचनात्मकता बढ़ेगी। शेर मारकेट बढ़ने की संभावना है। बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अनाज और खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करते ही राशि के जातकों को अच्छा



धनलाभ हो सकता है।

14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर
सूर्य हर एक माह में अपनी राशि बदलते हैं। जिसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष में सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देते हैं। ज्योतिष में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा गया है। सूर्य शुभ होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य के मीन से निकलकर मेष राशि में गोचर के साथ मीन मलमास समाप्त हो जायेगा और इसकी वजह से रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि फिर से शुरू हो जाएंगे।

19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर

रविवार 19 अप्रैल दोपहर 3:28 बजे शुक्र ग्रह अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश



डॉ. अनीष व्यास
भविष्यवाक्ता और कुण्डली विश्लेषक
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान,जयपुर-जोधपुर
मो.9460872809

असर पड़ता है। जिससे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। इस ग्रह के कारण शेयर मार्केट से जुड़े लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही शरीर में नसें, तंत्रिका तंत्र, गले और स्किन से जुड़ी बीमारी भी बुध की वजह से होती है। इस ग्रह के कारण तर्क शक्ति पर असर पड़ता है। साथ ही पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन और वकालात से जुड़े लोगों के कामकाज में भी बड़े बदलाव होते हैं।

यह होगा असर
देश की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। नए चेहरे और युवाओं को मौका मिलेगा। कुछ नेताओं को हानि होगी। पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ेगा।

अनचाही घटनाएं होंगी। वाद विवाद ज्यादा होंगे। भूकंप आगजनी रेल और वायुयान दुर्घटना होंगी। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन। सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी। बाजार और व्यापार को फायदा होगा। किसानों को फायदा होगा।

अन्न उत्पादन ज्यादा होगा। लोहा इस्पात मेडिकल और केमिकल्स व्यापार तरक्की करेंगे। आंखों एवं त्वचा के रोग बढ़ेंगे। सोने की कीमत और विदेशी करेंसी में उतार-चढ़ाव रहेगा। पेट्रोल, डीजल और तेल के दाम बढ़ने का अनुमान है। देश में विवाद होंगे। चोरी-डकैती, अपहरण और दुष्कर्म भी बढ़ने की आशंका है। जिससे लोगों में डर और तनाव रहेगा। नई-पुरानी बीमारियों से लोग परेशान हो सकते हैं। महंगाई और टैक्स बढ़ने के योग हैं।

उपाय
हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। मसूर की दाल का दान करें। शहद खाकर पर से निकलें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। भगवान श्री विष्णु की उपासना करें। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें ।

4 ग्रहों के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर असर
मेष: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बीमारी का अंदेशा है।
वृष: प्रमोशन के योग बनेंगे। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
मिथुन: रोजगार मिलेगा। समृद्धि बढ़ेगी।
कर्क: तनाव और दौड़-भाग रहेगी। समस्याएं सुलझ जाएंगी।

सिंह: मेहनत ज्यादा होगी और उसका फायदा मिलेगा।

कन्या: मांगलिक कामों के योग बनेंगे। खर्चा भी बढ़ेगा।

तुला: प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री के साथ ही रियल एस्टेट में निवेश के योग हैं।

वृश्चिक: परिवार से मदद मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु: मेहनत के मुताबिक सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता रहेगी।

मकर: खर्चा बढ़ेगा। सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी।

कुंभ: सेहत संबंधी परेशानी रहेगी। तनाव बढ़ेगा।

मीन: धन हानि और सेहत संबंधी परेशानी होगी। स्थान परिवर्तन के योग हैं।

वैशाख मास 3 अप्रैल से आरंभ, जानें महत्व और इस दौरान क्या करें क्या न करें

हिंदू नव वर्ष का दूसरा महीना वैशाख का होता है। चैत्र मास के बाद वैशाख मास का आरंभ हो जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस महीने में इनकी पूजा करने के विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य आदि कार्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित राकेश झा से कि वैशाख मास का आरंभ कब से हो रहा है और इस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानें वैशाख मास आरंभ होने की तारीख और नियम।

वैशाख मास 2026 का आरंभ कब?

पंचांग की गणना के अनुसार, वैशाख मास का आरंभ 3 अप्रैल से होने जा रहा है। दरअसल, 2 अप्रैल को सुबह में 7 बजकर 42 मिनट पर प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा और 3 तारीख को सुबह में 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार, 3 अप्रैल से ही वैशाख मास की शुरुआत होगी।

वैशाख मास का महत्व
स्कंद पुराण में भी वैशाख मास का विशेष महत्व बताया गया है। पुराण में



वैशाख मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है पुराण के अनुसार, नारदजी ने वैशाख मास का माहात्म्य इस तरह बताया है जैसे उपवास की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं, जीवन के समान कोई लाभ नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं होता, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है, वैसा ही वैशाख मास के जैसा दूसरा कोई पवित्र महीना नहीं होता है। इसलिए ही इस महीने में किए गए दान पुण्य, जप तप, उपवास आदि का विशेष महत्व बताया गया है।

वैशाख मास में क्या करें
वैशाख मास के दौरान लोगों को ठंडा पानी पिलाना पुण्य फलदायी माना जाता

है। इस दौरान पानी का दान करना पुण्यकारी माना गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी रखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है।

वैशाख मास में रोजाना शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

वैशाख मास में जरूरतमंद लोगों को जूते चप्पल और कपड़ों आदि का दान करें। ऐसा करना व्यक्ति को मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।

वैशाख मास में क्या न करें

वैशाख मास में सूर्योदय होने के बाद तक न सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करें।

तामसिक भोजन से परहेज करें। ऐसा करने से वैशाख मास में किए गए पुण्य फलों में कमी आती है। साथ ही सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।

वैशाख मास में भूलकर भी जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इस महीने में पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इस महीने में जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।

हनुमान जयंती पर मंगल गोचर का संयोग, वृषभ, मिथुन सहित अन्य राशियों के लिए बना मंगलकारी योग

मंगल गोचर 2 अप्रैल 2026, गुरुवार दे दिन होने जा रहा है। इस दिन संयोग से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। इस दिन हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। ऐसे में मंगल गोचर पर हनुमान जयंती का बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में मंगल प्रवेश करेंगे। हनुमान जी को मंगल का स्वामी भी कहा जाता है। ऐसे में ज्योतिष की दृष्टि से इसे कई राशियों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। मंगल गोचर के साथ हनुमान जयंती का संयोग वृश्चिक सहित 5 राशियों के लिए फलदायी रहने वाली है। इन राशियों को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।

वृषभ राशि : मेहनत का फल प्राप्त होगा
वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर इनकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा। ऐसे में कमाई के घर में मंगल का आना इनके लिए लाभ का संयोग निर्मित करेगा। ऊर्जा और उत्साह का संचार होने से कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और हनुमानजी की कृपा का लाभ भी इनको प्राप्त होता रहेगा। आप इस दौरान भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़े काम में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक संबंध आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा।



हनुमान जयंती पर मंगल गोचर

मिथुन राशि : नौकरी में सफलता मिलेगी
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके दसवें भाव में होने जा रहा है। हनुमान जयंती के दिन मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों को मेहनत का फल दिलाएगा। व्यवसाय और नौकरी करने वाले जातकों को सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ा समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती दिख रही है। यह समय समाज में आपको मान-सम्मान दिलाने वाला रहेगा।
कर्क राशि : अचानक बड़ी सफलता प्राप्त होगी
कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर नौवें भाव को प्रभावित करेगा। आपकी राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। इस दौरान आपको अचानक कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। लंबी दूरी की

यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिल सकता है। तीर्थ यात्रा पर जानें का सौभाग्य भी मिल सकता है। इस अवधि के दौरान पिता के साथ आपके संबंध भी अधिक प्रगाढ़ होंगे।

वृश्चिक राशि : अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे

वृश्चिक राशि वालों के पांचवें भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। इस दौरान आपकी राशि के जातकों

पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी। इस दौरान प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विवाहित लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। अचानक धन मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी के आशीर्वाद के आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होने लगेंगे।

मकर राशि : बाधाओं से छुटकारा मिलेगा

मंगल का गोचर आपकी राशि के तीसरे भाव में होने जा रहा है। ऐसे में मंगल का गोचर आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। इस दौरान आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। मंगल शत्रु पर विजय दिलाता है और हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। ऐसे में दोनों का मेल आपको बाधाओं से छुटकारा दिलाएगा। निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी रिस्क लेने की क्षमता आपको लाभ दिलाने का काम करेगी।

हनुमान जयंती साल में दो बार मनाई जाती है, जानें कब और क्यों दो बार मानते हैं हनुमानजी का जन्मदिन

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल, गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसके अलावा, साल में एक बार और भी हनुमानजी का जन्मदिन मनाया जाता है। जिसे हनुमान जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। हनुमान जयंती साल में दो बार मनाने के पीछे एक कथा छिपी हुई है। इसके मुख्य रूप से दो कारण बताए जाते हैं।
हनुमान जयंती दो बार कब-कब मनाई जाती है?
चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो हनुमान जयंती पड़ती है उसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 2 अप्रैल, गुरुवार को पड़ रही है। मान्यता है की इसी दिन पवन पुत्र हनुमानजी को नया जीवन प्राप्त हुआ था। ऐसे में जीवन पाने के साथ अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। वहीं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमानजी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत के लोग हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार मनाते हैं। पंचांग के अनुसार, इस साल 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 49 मिनट के बाद से चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में उत्तर भारत के मतानुसार इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
हनुमान जयंती साल में दो बार क्यों मनाई जाती है?
हनुमान का जन्मदिन दो बार मनाने के पीछे खास वजह बताई



पूरे ब्रह्मांड पर संकट आया तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने के बाद ब्रह्माजी ने भगवान हनुमान को दूसरा जीवन दिया। सभी देवताओं ने उन्हें कई प्रकार शक्तियां भी दी थीं। मान्यता है की जिस दिन हनुमानजी को दूसरा जीवन प्राप्त हुआ था उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा, पौराणिक कथाओं में बताया गया है की देवी सीता और भगवान राम ने बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसी के चलते कार्तिक माह में भी हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है।

सुबह-शाम भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो बढ़ सकती है आर्थिक परेशानी

वास्तु शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर की ऊर्जा हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो घर में नकारात्मक वातावरण पैदा कर सकती हैं। खासतौर पर सुबह और शाम का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन समयों में की गई छोटी गलतियां धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन पर असर डाल सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन आदतों को समय रहते सुधारा जाए, ताकि घर में सकारात्मकता और स्थिरता बनी रहे।

तुलसी से जुड़ी सावधानी

घर में तुलसी का पौधा शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं होता। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। बेहतर यह माना जाता है कि सुबह के समय ही पूजा के लिए आवश्यक पत्ते ले लिए जाएं, जिससे दिनभर घर में शांति और संतुलन बना रहे।

शाम के समय सफाई से बचें

वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद घर की सफाई या कूड़ा बाहर फेंकना अच्छा नहीं माना जाता। यह समय घर में ऊर्जा के स्थिर होने का होता है। ऐसे में सफाई करने से सकारात्मकता भी बाहर चली जाती है। इसलिए घर की सफाई सुबह के समय करना अधिक उपयुक्त माना जाता है, जिससे दिनभर अच्छा वातावरण बना रहे।

शाम को सोने की आदत

शाम का समय दिन और रात के बीच का संक्रमण काल होता है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान सोना सुस्ती और नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। इसके बजाय इस समय को परिवार के साथ बिताना या शांत वातावरण में बैठना मानसिक संतुलन के लिए बेहतर माना जाता है।

धन से जुड़े निर्णय का समय

आर्थिक मामलों में सही समय का चयन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष दिनों में धन से जुड़े कार्य करना अधिक अनुकूल होता है। इससे निर्णयों में स्थिरता आती है

और अनावश्यक जोखिम से बचाव होता है।

घर की दीवारों और फर्श का ध्यान

घर की साफ-सुथरी दीवारें और व्यवस्थित फर्श सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। दीवारों पर अनावश्यक निशान या गंदगी घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए घर को साफ और व्यवस्थित रखना मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है।

सुबह की शुरुआत साफ-सफाई से करें

दिन की शुरुआत घर की सफाई से करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। सुबह झाड़ू लगाने से रातभर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में ताजगी आती है। इसके बाद किए गए कार्य अधिक प्रभावी और सकारात्मक परिणाम देने वाले माने जाते हैं।

अंततः यह समझना जरूरी है कि जीवन में बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं। यदि रोजमर्रा की दिनचर्या में इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो घर का वातावरण संतुलित और सकारात्मक बना सकता है, जिससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए कानून का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले अपराधियों के लिए क्रिमिक दंड का प्रावधान करना है। कानून मंत्रालय ने 30 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विपक्षी सांसदों ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें समलैंगिक पुरुषों (गै) और समलैंगिक महिलाओं (लेस्बियन) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक में यह निर्धारित करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं। इस प्रावधान को लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कानून मंत्रालय की 30 मार्च की अधिसूचना के अनुसार, संशोधित कानून केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित की गई तिथि से लागू होगा।

उत्कल दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों को दी बधाई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओडिशा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य संस्कृति व आध्यात्मिक महानता के शाश्वत प्रतीक के रूप में गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्कल दिवस के विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता के शाश्वत प्रतीक के रूप में गर्व से खड़ा है। ओडिया संगीत, कला और साहित्य ने भारत को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। ओडिशा के लोग, जो अपने दृढ़ संकल्प, सादगी और प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ओडिशा प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से राज्य के लोगों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

शुभेंदु अधिकारी आज, ममता आठ को करेंगी नामांकन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्रु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है। शुभेंदु दो अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नामांकन भरेंगे, जिसे भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, ममता आठ अप्रैल को कालीघाट से शक्ति जुलूस निकालकर पर्चा दाखिल करेंगी। इधर, भाजपा ने 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। मनुआ बहुल बागदा सीट से केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। उनका मुकाबला तुणमूल की मधुपर्णा ठाकुर से होगा, जो उनके परिवार की ही सदस्य हैं। वहीं, चौरंगी से पूर्व कांग्रेसी संतोष पाठक और सोनारपुर उत्तर से पूर्व आईपीएस देवशीष धर को टिकट मिला है। यहाँ 23 और 29 अप्रैल को मतदान है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी दो अप्रैल को केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे।

सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु चुनावों से पहले बड़े वादे किए

चेन्नई। तमिलनाडु में चुनावी बिगुल फूँकते हुए डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को तिरुचिरापल्ली से अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। करुणानिधि का बेटा हूँ के उद्घोष के साथ स्टालिन ने आगामी चुनावों के लिए लोकलुभावन वादों का पिटाया खोलते हुए विशेष रूप से किसानों और महिलाओं को साधने की कोशिश की है। खेती-किसानी को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री ने दो बड़ी घोषणाएं कीं। सत्ता में वापसी पर राज्य के 20 लाख किसानों को मुफ्त पंपसेट देने का वादा किया गया है। किसानों को राहत देते हुए स्टालिन ने आश्वासन दिया कि धान की खरीद 3,500 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंची दर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमके सरकार बनने के तुरंत बाद, तिरुचि क्षेत्र में एक बड़ी लाइब्रेरी, TIDEL पार्क और ओलंपिक अकादमी शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तिरुचिरापल्ली को राजधानी चेन्नई के बराबर विकसित किया जा रहा है।

निशिकांत ने बिजू पटनायक पर टिप्पणी के लिए मांगी माफी

नईदिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक पर अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद बिना शर्त माफी जारी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए, नेहरू-गांधी परिवार की उपलब्धियों, विशेष रूप से भारत के अग्रणी नेताओं में से एक, पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के संदर्भ में मेरी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया। सबसे पहले, यह बयान मेरा निजी विचार है। नेहरू जी के बारे में मेरे विचारों को बिजू बाबू के बारे में गलत समझा गया। बिजू बाबू हमेशा से हमारे लिए एक महान राजनेता रहे हैं और रहेंगे। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। यह विवाद 27 मार्च को निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयानों से उभरा है, जिसमें उन्होंने 1960 के दशक में भारत की विदेश और रक्षा नीतियों के बारे में कई आरोप लगाए।

एनडीए की हैट्टिक पकड़ी, असम से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला

घुसपैठियों को बसाना चाहती है कांग्रेस पार्टी

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि असम ने पिछले दस वर्षों में उल्लेखनीय विकास देखा है और उन्हें विश्वास है कि राज्य की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। गोगमुख में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों का उत्साह निरंतर विकास और स्थिरता के प्रति उनके समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यह चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को आकार देगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने का है... भाजपा असम में फिर से सरकार बनाएगी और हैट्टिक बनाएगी। उनकी ये टिप्पणियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य भर में पार्टी के प्रचार अभियान तेज करने के बीच आई, जो 9 अप्रैल को होने वाले हैं। मोदी ने कहा कि असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जनसमुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों-बेटियों का ये आशीर्वाद, ये प्यार इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्टिक पकड़ी है। उन्होंने कहा कि आप सबसे आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्टिक बनाने का अवसर मिला। आप सबसे आशीर्वाद से इस मैदान में भी हैट्टिक लगाने का अवसर मिला है, मैं यहां तीसरी बार आया हूं। और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्टिक बनाने वाली है।

मोदी ने कहा कि पहले सर्वानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हिमंता विश्व शर्मा जी की अगुवाई में असम ने बीते 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम के ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार भाजपा-एनडीए सरकार की हैट्टिक लगनी तय है। और कांग्रेस



की पराजय की हैट्टिक भी तय है। और कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय की संचुरी लगने वाली है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बैदेउ बन चुकी हैं। कल असम भाजपा ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बैदेउ बनाने का प्रयास करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में समान नागरिक संहिता लागू करना और हमारे आदिवासी समाज, छठी अनुसूची क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, असम की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना...ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन भाजपा-एनडीए सरकार का निरन्तर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। भाजपा सरकार सैंकड़ों करोड़ रुपये यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है।

मोदी ने कहा कि एक समय था, जब

दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। अब असम को दुनिया, चाय के साथ-साथ चिप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं, जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फोन हों, गाड़ियां हों, टीवी, फ्रिज हों, ये सभी सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं। यही विकसित असम का हमारा रोडमप है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप यहां फिर से ऋद्धकसरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा। और ये आपको मोदी की गारंटी है!

विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा सत्ता की राजनीति और अपना परिवार ही पहला रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई हैं, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।6-7 दशक में असम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज हैं और 10 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां की मूल संताओं को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। भाजपा-एनडीए सरकार... किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगी। अवैध कब्जे के खिलाफ, भाजपा-एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी... ये मोदी की गारंटी है।

सैंसेक्स 1186 अंक चढ़ा निफ्टी 22679 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव रख के बीच भारतीय शेयर बाजार नए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दिन यानी बुधवार (1 अप्रैल) को बढ़त के साथ खुले। डेक्स हैवीवेट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एलएंडपी के शेयरों में तेजी से इंडेक्स को चढ़ने में मदद मिली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 73,762 अंक पर खुला। जबकि सोमवार को यह 71,947 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 73,964 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 1186.77 अंक या 1.65 प्रतिशत की बढ़त लेकर 73,134.32 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 22,899 पर खुला। यह सोमवार को 22,331 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 22,941 अंक के हाई लेवल तक गया। लेकिन अंत में 348 अंक या 1.56 फीसदी की बढ़त के साथ 22,679 पर बंद हुआ।

राज कुमार सिंह

कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, नोरो बांसुरी बजा रहा था। वैसा ही दृश्य हाल में अमरीका में दिखा, जब मध्य पूर्व की जंग की आग में झुलसती दुनिया से बेपरवाह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निवेशकों को संबोधित करने के बाद अपनी बालकनी में ड्रांस कर रहे थे। समझौता वार्ता जारी होने के दावों के बीच भी ट्रम्प द्वारा ईरान को धमकाना जारी है, तो इसराईल-अमरीका और ईरान के बीच जंग भी कमजोर तो हररिज नहीं पड़ी। बदलते बयानों और दावों के पीछे का खेल तो ट्रम्प ही बेहतर जानते होंगे, पर युद्ध जिस तरह और अधिक आक्रामक हो रहा है, वह वैश्विक स्थिरता और शांति, खासकर ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौतियों के और दुष्कर होने का ही संकेत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, खासकर तेल और गैस के लिए आयात पर

एटीएफ की कीमतों में 115% नहीं 8.5% की हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में 100% की अधिक की बढ़ोतरी को लेकर जताई जा रही आशंका गलत साबित हुई। पहले खबरें आई थीं कि एटीएफ की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़कर दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे काफी कम है। एटीएफ की कीमतों में लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है और वर्तमान कीमत करीब 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और होम्लूज जलदमस्कृत्य के बंद होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के चलते 1 अप्रैल से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका थी।

कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकारी कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 19 किलो सिलिंडर पर की गई है। हालांकि, सरकारी कंपनियों की ओर से घरेलू सिलिंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की दरें पहले के जैसी ही हैं। कमर्शियल सिलिंडरों के दामों में हुई यह वृद्धि सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी का नतीजा है। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत अब 2,078.50 रुपये हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले एक मार्च को 19 किलोग्राम के सिलिंडर पर 114.5 रुपये की वृद्धि की थी। हालांकि, सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जीडीपी में 2025 की बढ़ोतरी से ज्यादा का नुकसान

न्यूयॉर्क। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव, अब पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, वैश्विक स्तर पर उसका उतना ही गहरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम एशिया के देशों ने बीते साल यानी 2025 में जितनी कुल जीडीपी बढ़ोतरी की थी, ईरान युद्ध में उससे ज्यादा का अब तक नुकसान हो चुका है। साथ ही ये भी कहा गया है कि युद्ध जैसे-जैसे लंबा खिंचेगा, ये नुकसान और बढ़ता जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, इस युद्ध से पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी सामूहिक जीडीपी का 3.7 से 6 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है। यह नुकसान अधिकतम 194 अरब डॉलर तक हो सकता है।

स्टेल प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर रवा इतिहास

वेलिंगटन। अमेलिया केर की कप्तानी में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर शानदार जीत दंड की। तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम ने निर्धारित 50 ओवर के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 346 रन बनाए। इसके जवाब में 2 गेंद बाकी रहते हुए न्यूजीलैंड महिला टीम ने लक्ष्य हासिल किया और दो विकेट से मैच अपने पाले में किया। इस मैच में मिली जीत के साथ ही न्यूजीलैंड महिला टीम ने इतिहास रच दिया। ये महिला क्रिकेट टीम के वनडे इतिहास की ससबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बन गया है, जो न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। इस दौरान टीम ने भारतीय टीम का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बता दें कि, पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका महिला टीम की ओर से कसान लॉरा वोलवार्ट ने 74 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। उनके अलावा ऐनी बॉश ने 90 गेंद पर 91 रन की पारी खेली। सूने लूस ने 40 रन, जबकि विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा ने 37 रन और क्लो ट्राईऑन ने 52 रन की नाबाद पारी खेली। इन पारियों के दम पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 347 रन का लक्ष्य मिला। क्वीकी टीम की ओर से ब्रियरने इलिंग ने 3 विकेट, जबकि केले नाइट ने दो विकेट झटके। एक विकेट जेस केर के नाम भी रहा। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की महिला टीम की ओर से कसान अमेलिया केर ने 139 गेंद पर 23 चौके और 1 छक्का लगाया और 179 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी के दम पर टीम को 8 विकेट के नुकसान पर 350 रन का स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। क्वीवी टीम ने दो गेंद बाकी रहते हुए ये लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड ने वनडे इतिहास के सबसे सफल रन चेज में से एक को अंजाम दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

युद्धोन्माद से गहिराता वैश्विक ऊर्जा संकट

राज कुमार सिंह

ही ज्यादा निर्भर है। इसलिए संकट विकराल होना ही है। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज इयूटी में कटौती जैसी जो संवेदनशीलता दिखाई है, वैसी इसराईल-अमरीका और ईरान युद्ध शुरू होने के सप्ताह भर में ही घरेलू सिलेंडर 55 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा करते समय नहीं दिखी।

पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर भीड़ अफवाह जनिात आशंकाओं का भी परिणाम मान लें। तो रसोई गैस बुकिंग की अंतराल अवधि बढ़ाने, कमर्शियल गैस की आपूर्ति कम करने और हवाई किराए की अधिकतम सीमा हटाने जैसे सरकार के कई फैसले यही बता रहे हैं कि भारत ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है। निजी तेल कंपनी निरारा एनर्जी ने तो दाम बढ़ा भी दिए हैं। अनुभव बताता है कि सरकारी तेल कंपनियां भी मूल्य वृद्धि के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न

होने का ही इंतजार कर रही हैं। एल.पी.जी. उत्पादन बढ़ाने के दावे राहत देते हैं, पर सवाल अनुचरित है कि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता थी तो उसके लिए संकटकाल की प्रतीक्षा क्यों? स्टेट ऑफ होम्लूज बंद होने के बावजूद वहां से भारत के हजारों का निकलना तथा ऊर्जा आपूर्ति स्रोतों का विस्तार राहतकारी है लेकिन खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि इससे हम संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट से बच जाएंगे। हमें आत्ममुग्धता से उबर कर चुनौतियों से निपटने की तैयारियां करनी चाहिए।

तेल और गैस आपूर्ति का संकट बहुआयामी है, जिसका असर छोटे उद्योगों से ले कर खाद्य सुरक्षा तक पड़ सकता है। मझोले और छोटे उद्योग बंद होने तथा परिणामस्वरूप प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबरें आने भी लगी हैं। इस सबसे



नागरिकों का जीवन-यापन तो दुश्धार हो ही जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा। अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करने वाले भारत के लिए संकट की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपूर्ति स्रोतों के विस्तार के जरिए जरूरत के मुताबिक आयात सुनिश्चित भी कर लें तो सवाल है क्या डेढ़ गुनी या दो गुनी कीमत पर पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस खरीदने की ऋय शक्ति हमारे नागरिकों की है? डॉलर के मुकाबले हर रोज रसतल में जा रहा रुपया मुश्किलें बढ़ाएगा ही। ईरान और रूस से ही हमें डॉलर में भुगतान किए बिना कच्चे तेल के आयात की सुविधा मिलती रही है। इस आश्रय संकट के लिए इसराईल-अमरीका और ईरान के अलावा शायद ही कोई और जिम्मेदार हो लेकिन

प्रभाव से कोई देश बच नहीं पाएगा। इसीलिए जानकार इस संकट की तुलना 1973 और 1979 के ऐतिहासिक ऊर्जा संकट से कर रहे हैं। उन दोनों अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के बीच भी मध्य-पूर्व में ही बोए गए थे। 6 अक्तूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने इसराईल पर हमला किया, जिसके बाद अमरीका ने इसराईल को सैन्य सहायता दी। अरब-इसराईल युद्ध में इसराईली सेना को पुनः आपूर्ति करने तथा युद्धोत्तर शांति वार्ता में लाभ प्राप्त करने की अमरीकी कवायद के प्रतिशोधस्वरूप ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक' के सदस्य अरब देशों ने अमरीका के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिए। अक्तूबर, 1973 से जनवरी, 1974 तक चले उस तेल संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गई थीं, जिसका परिणाम ईंधन की कमी और आर्थिक मंदी के रूप में सामने आया था।

भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान विभिन्न मंडलों में संपन्न



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत रायपुर जिले के विभिन्न मंडलों—तेलीबांधा, शंकरनगर, पुरानीबस्ती, सदर बाजार, सिविललाइन, भांडगांव, डी.डी. नगर,

तात्यापारा, रामनगर, टाटीबंध, बीरगांव, रायपुर ग्रामीण, भनपुरी, माना मंडल, मोवा मंडल एवं मां बंजारी मंडल—में प्रशिक्षण वर्गों का सफल आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण वर्गों में कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति, विचारधारा

एवं सेवा भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी गई जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित यह प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं के वैचारिक एवं संगठनात्मक विकास का सशक माध्यम है। उन्होंने एकात्म

मानववाद के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र प्रथम एवं अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं में अनुशासन, समर्पण एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जिससे संगठन और अधिक सशक्त बनता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने एवं बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान तात्यापारा मंडल में शिविर के समापन सत्र में छ.ग. शासन के कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समस्त मंडलों के प्रशिक्षण वर्गों में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संकल्प लिया कि वे पार्टी की कार्य पद्धति को अपनाकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

पश्चिम एशियाई संकट के बीच उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

रायपुर। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका - इज़राइल और ईरान के बीच तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच केन्द्र और राज्य सरकार ने किसानों को उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आर्बटित हुआ है। वर्तमान में गोदामों एवं समितियों में लगभग 7.48 लाख



मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी किसानों को पारदर्शिता के साथ पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद का आर्बटन सुनिश्चित हो।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की वरचुअल बैठक लेकर राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति, अद्यतन स्टॉक एवं वितरण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस वरचुअल बैठक में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, राज्य के कृषि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वरचुअल

रूप से शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री श्री नेताम ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा खरीफ सीजन -2026 के लिए कुल 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आर्बटित किया गया है, जिसमें यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख तथा एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि 30 मार्च 2026 की स्थिति में राज्य में कुल 7.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक में मौजूद है।

लोकभवन में मनाया गया विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज लोकभवन में 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विशेष रूप से उपस्थित थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस समारोह में राज्यपाल श्री डेका, अरूणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव, बिहार, राजस्थान और ओडिशा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि यह अवसर इन राज्यों की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक परंपराओं और विकास यात्रा को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य

विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना है जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है। राज्यपाल ने मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन-दीव की पर्यटन एवं औद्योगिक विशेषताओं, बिहार के लोगों का अर्थव्यवस्था एवं विकास में योगदान, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत, राजस्थान के लोगों के व्यापारिक उन्नति और शौर्य परंपरा तथा ओडिशा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत समानताएं हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारत की विविधता की उसकी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत बनाते हैं।

जहां कभी नक्सलवाद का था बोलबाला, वहां अब खेलो का हो रहा उदय

रायपुर। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने %खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026% के दौरान बुधवार को रायपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां के माहौल को ऊर्जा, आशा और बदलाव से भरपूर बताया। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि एथलीटों, स्थानीय समुदाय और इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मिली प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है। देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2,500 से ज्यादा एथलीट अलग-अलग खेलों में खेलते इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीमती खडसे ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, केंद्र सरकार की उस प्रतिक्रिया को दिखाता है जिसके



तहत आदिवासी युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए एक मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह खेल एक नई उम्मीद है और यह संकेत कि उनकी काबिलियत को पहचाना जा रहा है और उस पर सबसे ऊंचे स्तर पर निवेश किया जा रहा है।

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री ने कहा, %एक समय था जब छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, और यहां के लोगों को एक पिछड़ा समुदाय

माना जाता था। आज, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए एक नई दिशा खुल रही है। नक्सलवाद का खाम्ता हो चुका है और खेल के माध्यम से, इस धरती के युवा अब अपनी ऊर्जा और क्षमता को सामने ला सकते हैं और देश के लिए खेल सकते हैं।% खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 को एक ऐतिहासिक पहल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, गुहमंजी अमित शाह (जिन्होंने पूरे देश से नक्सलवाद के खाम्ते की घोषणा की है), कैबिनेट मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और पूरी साईं टीम को दिया। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि इन खेलों में हिस्सा लेने वाले कई एथलीट आगे चलकर ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक जीतेंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

रमन सिंह के शाह को लिखे पत्र पर दीपक बैज का पलटवार

रायपुर। डॉ रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नक्सलवाद की समाप्ति के लिये उनका यशोगान करते हुए एक पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रमन सिंह ने नक्सलवाद के लिये तत्कालीन केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की खेती करने का श्रेय डॉ. रमन सिंह को जाता है, 2003 से 2018 तक वह मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में जो नक्सलवाद बस्तर के तीन ब्लॉकों तक था, वह फैलकर प्रदेश के 14 जिलों तक पहुंच गया। राजधानी बस्तर तक नक्सलवाद की धमक पहुंच गयी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि टाइमेटला से लेकर झीरम जैसे दुर्दांत नरसंहार का कलंक जिसके माथे में लगा हुआ है वो रमन सिंह बेशर्मीपूर्वक अपनी जिम्मेदारी तत्कालीन केंद्र सरकार पर थोप रहे थे। जबकि बस्तर के नक्सल क्षेत्रों में तैनात किये गये केन्द्रीय सुरक्षा बल मनमोहन सरकार के समय ही बस्तर आये थे। मोदी सरकार ने एक भी बटालियन की बढ़ोतरी नहीं किया था। रमन सिंह अपने पत्र में नक्सलवाद समाप्ति के लिये विष्णुदेव साय और विजय शर्मा का जिक्र तक करना भी जरूरी नहीं समझा, ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को दिखाता है।



शराबबंदी छोड़ शराब की कमाई बढ़ाने में लगी: शुक्ला

रायपुर। शराब की कीमतें बढ़ाने और शराब को प्लास्टिक की बोतल में बेचने के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शराब के दाम बढ़ाना एवं प्लास्टिक के बोतल में शराब बेचना गलत है। भाजपा की सरकार शराब की काली कमाई करने में लगी हुई है। जनता को लूटने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा सरकार पहले तो लोगों को शराबी बनाया गया, शराब की लत लगाया गया, शराब की खपत बढ़ाई गयी, लोग शराब पीने लगे तो शराब के रेट बढ़ाकर जनता को लूटने लगे। 5 साल तक शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुनाफा कमाने के लिये प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने जा रही है। प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने से प्लास्टिक का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य में पड़ेगा ही और प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकने से कैंसर जैसे घातक बीमारी भी हो सकती है। 5 साल तक शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता को लूटकर शराब से काली कमाई करके अपने जेब भरने में लगे हुये है। रहकर शराबबंदी की बड़ी-बड़ी बात करने वाली भाजपा सरकार में आने के बाद शराब की काली कमाई में लग गई है।



गांव बस्ती चलो अभियान कांग्रेस की नकल: ठाकुर

रायपुर। भाजपा के स्थापना दिवस पर गांव बस्ती चलो अभियान शुरू करने पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की गांव चलो अभियान की नकल कर, अब भाजपा अपने स्थापना दिवस से गांव-बस्ती चलो अभियान शुरू कर रही है। पहले से ही कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत ग्राम वाई बूथ समिति गठन करने गांव-गांव अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एवं वरिष्ठ नेतागण गांव-गांव जा रहे है, संगठन का विस्तार कर रहे है, जनता से संवाद कर रहे है। जनता का आक्रोश भाजपा सरकार के प्रति है, हर वर्ग में नाराजगी है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस महंगी बिजली, धान खरीदी में अनिमियता, रोजगार, बढ़ते अपराध, बढ़ते नशाखोरी, भ्रष्टाचार, सड़को की जर्जर हालत, पेयजल की समस्या, लचर शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बंद पड़े विकास कार्य को शुरू करने की क्यों सौंप नहीं रही है? जितने लंबे समय तक धान संग्रहण केन्द्रों में रखा जायेगा, उतना ही भ्रष्टाचार का जोखिम बढ़ेगा और उतना ही धान खराब होने और वजन कम होने का खतरा रहेगा, यानी हर दिन के साथ सरकार खुद अपने नुकसान को बढ़ा रही है।



धान संग्रहण केन्द्रों में लाखों टन धान पड़ा सूख रहा: वर्मा

रायपुर। कांग्रेस ने संग्रहण केन्द्रों पर धान खुले में पड़े रहने पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जितने लंबे समय तक धान खुले में पड़े रहेगा, नमी का मौसम का असर धान पर पड़ेगा। गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ेगी तथा एक बार फिर से चूहों पर जिम्मेदारी थोपी जायेगी। भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केन्द्रों से मीलरों को मीलिंग के लिये धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में निलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केन्द्रों में जमा पड़ा है। पुरे प्रदेश में 24 लाख टन से अधिक धान खुले में पड़ा है। अकेले बेमेतरा जिले में 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान जाम पड़ा हुआ है। जब मीलर सरकार से अनुबंध के तहत धान लेने को तैयार है। फिर सरकार धान को मिलर्स को क्यों सौंप नहीं रही है? जितने लंबे समय तक धान संग्रहण केन्द्रों में रखा जायेगा, उतना ही भ्रष्टाचार का जोखिम बढ़ेगा और उतना ही धान खराब होने और वजन कम होने का खतरा रहेगा, यानी हर दिन के साथ सरकार खुद अपने नुकसान को बढ़ा रही है।



मोदी सरकार की विफलता के कारण महंगाई बढ़ गयी : वंदना

रायपुर। मोदी सरकार की विफलता के कारण महंगाई बढ़ गयी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि आज ही मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस के दाम में 218 रु. की बढ़ोतरी कर दिया। इसके पहले तीन महीने में कमर्शियल गैस के दाम में 525 रु. की बढ़ोतरी हुई थी, पिछले हफ्ते ही मोदी सरकार ने घरेलू गैस के दाम में 62 रु की बढ़ोतरी कर दिया। सरकार ने खूब वाहवाही लिया कि पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज कम कर दिया लेकिन आज ही पेट्रोल के दाम में 1 रु. से 2 रु. की बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में हुई है। नायरा के पेट्रोल पंप में तो यह बढ़ोतरी 4 रु. की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि खाद्य तेल, मावा, राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ गये है। दूध के दाम भी बढ़ गये। आम आदमी के किचन का बजट मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। खाद्य तेल को 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने में 70 साल लग गए थे, लेकिन मोदी राज के चंद दिनों में ही 200 पार हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर जो भाजपाइयों को 400 रुपए में महंगा लगाता था, उसे 900-1000 तक पहुंचा दिए, कमिश्नल गैस सिलेण्डर के दाम आज से 1580 से बढ़कर 1691 हो गया है।



हिंसा छोड़कर नई दिशा, नई राह की ओर बढ़ रहे कदम

रायपुर। मानव समाज का सबसे उत्कृष्ट पहलू सकारात्मक परिवर्तन है, जिससे जीवन में नवाचार और नए विचार जन्म लेते हैं। ऐसा ही बदलाव आत्मसमर्पित माओवादियों के जीवन में दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर उन्हें पहले प्रशिक्षित किया गया और अब कुशल होने के बाद रोजगार भी मुहैया हो रहा है। आत्मसमर्पित माओवादियों को भानुप्रतापपुर के ग्राम मुल्ला (चौगेल) के कैम्प में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पारंगत होने के बाद प्रशासन के प्रयासों से रोजगार भी दिलाया जा रहा है। मुख्यधारा में लौटकर प्रशिक्षण के



उपरांत रोजगार प्रदान करने के मामले में उत्तर बस्तर कांकेर पहला जिला है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी ने आज कलेक्टर कक्ष में आज सुबह 04 आत्मसमर्पित माओवादी व

पीड़ितों को नियुक्ति पत्र सौंपा तथा उन्हें नई शुरूआत के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। इनमें पुनर्वासित सगनूराम आंचला एवं नक्सल पीड़ित रोशन नेताम, बीरसिंह मंडावी और संजय नेताम शामिल थे। इन सभी को निजी फर्म का नियुक्ति पत्र प्रदाय किया गया,

जहां 15 हजार रूपए प्रतिमाहा प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल एवं पारंगत बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद जिला प्रशासन द्वारा रोजगार भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़ गया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अहमियत मुख्यधारा में जुड़ने के बाद ही पता चली। जीवन के अलग-अलग रंगों व वास्तविक खुशियों की पहचान अब जाकर हुई। श्री आंचला ने शासन-प्रशासन का आधार मानते हुए कहा कि जीने का असली मकसद अब मिला है। इसी तरह माओवाद पीड़ित बीरसिंह मंडावी ने कहा कि ग्राम मुल्ला (चौगेल) के कैम्प में

पुनर्जीवन मिला है, जहां निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल एवं पारंगत बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद जिला प्रशासन द्वारा रोजगार भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़ गया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अहमियत मुख्यधारा में जुड़ने के बाद ही पता चली। जीवन के अलग-अलग रंगों व वास्तविक खुशियों की पहचान अब जाकर हुई। श्री आंचला ने शासन-प्रशासन का आधार मानते हुए कहा कि जीने का असली मकसद अब मिला है। इस प्रकार शासन की सकारात्मक पहल का प्रत्यक्ष लाभ पुनर्वासितों व पीड़ितों को मिल रहा है।

एलपीजी बुकिंग संख्या में आई कमी, आपूर्ति व्यवस्था धीरे-धीरे हो रही सामान्य

रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के चलते प्रदेश में 6 मार्च से 16 मार्च के दौरान दैनिक एलपीजी बुकिंग में आई असामान्य वृद्धि और धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। सामान्यतः प्रदेश में एक दिन में औसत 74 हजार एलपीजी की बुकिंग दर्ज होती थी, जो कि 6 मार्च के बाद अज्ञात बढ़कर 1.30 लाख तक पहुंच गई थी। किन्तु राज्य शासन तथा ऑयल कंपनियों की सतत मॉनिटरिंग और कार्रवाई आपूर्ति में वृद्धि के कारण दैनिक एलपीजी बुकिंग में पिछले दो सप्ताह में लगातार कमी परिलक्षित हुई है।



खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाल ने जानकारी दी कि राज्य शासन द्वारा खाद्य विभाग एवं ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा दैनिक बुकिंग, जिलों को प्रदाय एलपीजी रिफिल सिलेंडर, वितरित सिलेंडर, पेंडिंग बुकिंग संख्या और जिलों में उपलब्ध एलपीजी रिफिल सिलेंडर के स्टॉक की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इसके तहत पेंडिंग बुकिंग को क्लीयर करने हेतु जिलों को मांग के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर प्रदाय किया जा रहा है।साथ ही घरेलू एलपीजी के

दुरुपयोग को रोकने हेतु संधिध स्थानों की जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 97 छापों में 3,847 सिलेंडर जप्त किए गए हैं तथा 9 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। राज्य शासन के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 16 मार्च की लंबित बुकिंग संख्या की तुलना में 31 मार्च तक लंबित बुकिंग संख्या में 1.08 लाख की कमी आई है, जिससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। राज्य में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आम उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध राज्य शासन द्वारा किए गए हैं।